वर्ष : 17 ❖ अंक : 253 ❖ पृष्ठ : 08 ❖ मूल्य : ₹ 3.00 ❖ आरएनआई सं. SIKHIN/2006/17890 ❖ www.anugamini.com

सिक्किम से प्रकाशित प्रथम हिन्दी दैनिक

अनुगामिनी

गंगटोक
शुक्रवार, 21 अप्रैल 2023

आधुनिक समस्याओं का समाधान पहले ही दे गए बुद्ध : पीएम मोदी 3 | मानहानि केस में राहुल गांधी की सूरत कोर्ट से याचिका खारिज 8

तीन ग्राम पंचायतों के लिए उपचुनाव सम्पन्न

एक प्रादेशिक समष्टि के लिए भी हुआ मतदान

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 20 अप्रैल । सिक्किम के तीन ग्राम पंचायत वार्डों और एक जिला प्रादेशिक समष्टि में उपचुनाव आज शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। तीन ग्राम पंचायत वार्डों में पाकिम जिलान्तर्गत लिंके परखा जीपीयू के लिंके वार्ड 78 प्रतिशत मतदान हुआ है। वहीं नामची जिलान्तर्गत दो वार्डों लोअर गांगयांग एवं अपर शालमथांग वार्ड में क्रमश: 77.02 प्रतिशत एवं 66.91 प्रतिशत मतदान हुआ है। वहीं मंगन जिला के नामोक-स्वाएम प्रादेशिक समष्टि उपचुनाव में सर्वाधिक 78.44 प्रतिशत मतदान होने की खबर है। इसके अलावा दो वार्डों में उपचुनाव में उम्मीदवारों के निर्विरोध विजयी होने की भी खबर है। इनमें मंगन जिला में गैरी वार्ड और गेजिंग जिला में लोअर टिकज्या वार्ड शामिल हैं। तीन वार्डों एवं एक जिला प्रादेशिक समष्टि उपचुनाव के लिए मतों की गिनती कल की जाएगी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार पाकिम के लिंके परखा वार्ड में नवंबर 2022 में हुए पंचायत चुनाव का बहिष्कार किया गया था। भूटिया-लेप्चा बहुल इस सीट को ओबीसी में बदलने के कारण ऐसा किया गया था। वार्ड के कुल 462 योग्य मतदाताओं में से 95 प्रतिशत भूटिया लेप्चा (बीएल) समुदाय के हैं, जबकि शेष 5 प्रतिशत ओबीसी वर्ग के हैं। आज हुए चुनाव में 360 मतदाताओं ने दो उम्मीदवारों हरि माया शर्मा और रूपा देवी छेत्री के पक्ष में वोट डाला। हरि माया शर्मा ने दो बार पंचायत के रूप में कार्य किया है और वह पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी हैं।

पत्रकारों से बात करते हुए शर्मा ने कहा कि उन्हें आरक्षण को लेकर विवाद के बीच नवंबर के चुनावों में उम्मीदवारी हेतु आमंत्रित किया गया था। हालांकि, उस समय जनता को एसटी सीट के नुकसान का डर देखते हुए उन्होंने इसका विरोध नहीं किया था। हालांकि, जब उन्हें अपना उम्मीदवार नहीं मिला तो लोगों ने उनसे चुनाव लड़ने का अनुरोध किया। शर्मा के अनुसार, निर्वाचित होने पर वह जनता की चिंताओं को और भी प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाएंगी। उन्होंने कहा, मेरा लक्ष्य जनता के बीच कोई झगड़ा न होने देना और मिलकर विकास सुनिश्चित करना है।

वहीं लिंके वार्ड की एक अन्य उम्मीदवार रूपा देवी छेत्री का लक्ष्य निर्वाचित होने पर लिंके की जनता की सेवा करना है। वह एक गरीब परिवार से आती हैं और पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। उन्होंने कहा, मैं खुद को विजयी उम्मीदवार नहीं मान रहा हूं, लेकिन मुझे अब तक जो समर्थन मिला है, वह संतोषजनक है। मैं इस क्षेत्र में सड़कों की खराब स्थिति और अन्य समस्याओं से अवगत हूं और निर्वाचित होने पर उन्हें दूर करने का प्रयास करूंगी। गौरतलब है कि छेत्री ने पिछले साल पंचायत चुनाव के दौरान भूटिया-लेप्चा सीट आरक्षण का समर्थन किया था और चुनाव नहीं लड़ा था। हालांकि जब ओबीसी समुदाय को आरक्षण दिया गया तो उन्हें मौजूदा उपचुनाव में लड़ने का मौका मिला।

इधर लिंके वार्ड के एक स्थानीय मतदाता ने कहा कि पिछले चुनाव में भूटिया-लेप्चा के लिए आरक्षित इस सीट पर ओबीसी उम्मीदवार दिये जाने के कारण जनता ने चुनाव का बहिष्कार किया था। वहीं एक अन्य स्थानीय निवासी ने कहा कि जब आरक्षण का निर्णय किया गया था तो जनता ने सामूहिक रूप से चुनाव का बहिष्कार किया था। उनका कहना था कि कैसे 95 प्रतिशत एसटी मतदाताओं वाला एक वार्ड ओबीसी के लिए आरक्षित हो गया। लेकिन फैसला आए छह महीने बीत जाने के बावजूद आरक्षण ओबीसी बना रहा। ऐसे में लगातार चुनाव बहिष्कार करने को सरकार और चुनाव आयोग के विरोध के रूप में देखे जाने के कारण सरकार द्वारा उपचुनाव की अधिसूचना के बाद उसका पालन कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि जो हुआ है उससे जनता संतुष्ट नहीं है, क्योंकि इसे लोगों के आरक्षण के साथ अन्याय के रूप में देखा जाता है।

इसी बीच, आज राज्य चुनाव आयुक्त केसी लेप्चा ने चुनाव पर्यवेक्षकों और अन्य अधिकारियों के साथ लिंके में मतदान केंद्र का दौरा किया और मतदान प्रतिशत पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि दोपहर तक 462 योग्य मतदाताओं में से 307 मतदाताओं ने वोटिंग की थी। आरक्षण मुद्दे पर हमने संवैधानिक आदेश का पालन किया है और इन मामलों की अनदेखी नहीं कर सकते। रोटेशन की एक प्रणाली है जिसका हमें पालन करना है, और हमें बिना किसी बदलाव के चुनाव कराना है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि हम लोगों की भावनाओं को समझते हैं। वे शांतिप्रिय लोग हैं। हालांकि बहिष्कार के कारण वे विकास में छह महीने पीछे हट गए हैं। अब वे अपना नुकसान वापस पा सकते हैं।

उल्लेखनीय है कि, लिंके वार्ड के अलावा, नामची जिले में लोअर गांगयांग वार्ड में तीन उम्मीदवार और अपर शालमथांग वार्ड में दो उम्मीदवार मैदान में थे। वहीं मंगन के नामोक-स्वाएम प्रादेशिक समष्टि में दो उम्मीदवार थे।

सिक्किम के विकास के लिए बीजेपी की सरकार जरूरी : डीआर थापा

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 20 अप्रैल । भारतीय जनता पार्टी, सिक्किम की मंगन जिला स्तरीय समन्वय बैठक आज उत्तरी सिक्किम में मंगन के पास चांडे गांव में आयोजित की गई। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष डीआर थापा, उपाध्यक्ष अर्जुन राई, महामंत्री भरत दुलाल, जिलाध्यक्ष ताशी अंगडुप लेप्चा सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस अवसर पर मंगन जिलाध्यक्ष ताशी अंगडुप लेप्चा के नेतृत्व में आज जिला पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई जिसमें राम बहादुर लिम्बू महासचिव, सोनम तोपगे तमांग कोषाध्यक्ष, विभिन्न मोर्चा अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी सदस्य शामिल हैं।

सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष डीआर थापा ने नवनियुक्त अधिकारियों को बधाई दी और उनके सफल कार्यकाल की कामना की। अपने संबोधन में, अध्यक्ष थापा ने सिक्किम के आज के सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य में भारतीय जनता पार्टी की आवश्यकता पर प्रकाश डाला और कहा कि राज्य के सर्वांगीण विकास, सिक्किम के अस्तित्व और अनुच्छेद 371 एफ की पूर्ण सुरक्षा की मांगों को पूरा करने की क्षमता केवल भाजपा में है। उन्होंने सभी पदाधिकारियों का आह्वान किया कि वे पार्टी की नीति और सिद्धांतों के साथ-साथ केंद्र की मोदी सरकार के जनकल्याण और विकास कार्यक्रमों को लेकर जनता के बीच जाएं। आज केंद्र की भाजपा सरकार ने राज्य के लोगों के लिए घर-घर मुफ्त चावल से लेकर घर-घर पीने का पानी, गांव-गांव तक पीएमजीएसवाई सड़कें, बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय राजमार्ग, रोजगार और स्वरोजगार के अवसर, स्वास्थ्य सुविधा जैसी कई योजनाएं पहुंचाई हैं। सिक्किम केवल केंद्रीय योजनाओं पर चल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि घर-घर सभी सुविधाएं पहुंचाने वाली भाजपा को सिक्किम में भी एक और मौका दिया जाना चाहिए।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पार्टी उपाध्यक्ष अर्जुन राई ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को विभिन्न संगठनात्मक मुद्दों व दायित्वों से अवगत कराते हुए पार्टी की विचारधारा से अवगत कराया। इस मौके पर विभिन्न दलों को छोड़कर कई लोग भाजपा में शामिल हो गए।

सीएम ने की दलाई लामा से मुलाकात

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 20 अप्रैल । सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग (गोले) ने 19 अप्रैल को परम पावन 14वें दलाई लामा से नई दिल्ली में मुलाकात की और उनका आशीर्वाद मांगा। दलाई लामा के जुड़े वीडियो से संबंधित विवाद के बीच, सिक्किम के मुख्यमंत्री गोले ने आध्यात्मिक नेता को अपना समर्थन दिया है और कहा कि यह बौद्ध आध्यात्मिक नेता की छवि को धूमिल करने का एक दुर्भावनापूर्ण प्रयास है।

प्रेम सिंह तमांग (गोले)ने एक फेसबुक पोस्ट पर लिखा कि उन्होंने हमें और राज्य के सभी लोगों को अपने ज्ञान और दिव्य शिक्षाओं के साथ आशीर्वाद दिया और हमारा कुशलक्षेम पूछा।

सीएम गोले ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में आगे लिखा, बैठक के दौरान हमने उन्हें आगामी अक्टूबर महीने में सिक्किम आने का निमंत्रण दिया और उन्होंने सहर्ष हमारे निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। सिक्किम के लोगों की ओर से मैं उनके प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं और हमेशा उनकी तरह की चिंताओं और परोपकार के लिए ऋणी रहूंगा।

एसकेएम नारी मोर्चा ने दुष्कर्म व हत्या के आरोपी को फांसी देने की मांग की

राज्य का कोई वकील न लड़ें आरोपी का मुकदमा : कला राई

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 20 अप्रैल । राज्य की सत्ताधारी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा की महिला शाखा नारी शक्ति ने पांगथांग में 11 वर्षीय स्कूली छात्रा के साथ दुष्कर्म एवं उसकी हत्या के आरोपी प्रीतम शर्मा के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करते हुए मौत की सजा की मांग की है। गिरफ्तार आरोपी प्रीतम शर्मा बिहार का रहने वाला है और सिक्किम में ड्राइवर के रूप में काम करता था।

एसकेएम महिला शाखा प्रमुख पूजा शर्मा ने कल यहां आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन में मृतका एवं उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए हत्यारे को मृत्युदंड देने की मांग की। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए और इनके लिए जिम्मेदार अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने बताया कि घटना के विरोधस्वरूप एवं नाबालिग को न्याय दिलाने के लिए रविवार को एसकेएम नारी शक्ति की ओर से कैंडल मार्च निकाला जाएगा।

वहीं संगठन अध्यक्ष कला राई ने जोर देते हुए कहा कि आमलोगों को इस तरह के जघन्य अपराधों के बारे में पता होना चाहिए। उन्होंने राज्य के किसी भी वकील से इस मामले को न लेने का भी आग्रह किया। इसके साथ ही आरोपी का चेहरा आम जनता के सामने दिखाने की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि एक अपराधी हमेशा एक अपराधी होता है, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या पृष्ठभूमि का क्यों न हो। इस दौरान जिलाध्यक्ष चुंग चुंग भूटिया ने स्कूल सुरक्षा के मुद्दे पर बोलते हुए स्कूलों से करीब रहने वाले विद्यार्थियों को ही लेने को कहा। उन्होंने स्कूल सिक्योरिटी और माता-पिता को बच्चों की सुरक्षा हेतु और सजग रहने के बारे में कहा। एसकेएम महिला शाखा ने भविष्य में इस तरह की हत्याएं रोकने और पांगथांग मृतका को न्याय दिलाने हेतु अपनी प्रतिबद्धता दर्शायी है।

सिक्किम में बढ़ रहे हैं अपराधियों के हौसले : दिव्या शर्मा

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 20 अप्रैल । सिक्किम की विपक्षी एसडीएफ पार्टी ने हाल ही में पांगथांग में एक नाबालिग छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या की घटना को दिल्ली के निर्भया कांड के समान से बताते हुए राज्य में बेखौफ अपराधियों के बढ़ते हौसले के लिए राज्य की लचर कानून-व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया है। इसे लेकर पार्टी ने सत्ताधारी एसकेएम सरकार की तीखी आलोचना की है।

एसडीएफ की प्रसार महासचिव दिव्या शर्मा ने विज्ञप्ति में कहा कि अपराध और अपराधियों का कोई देश, जाति और लिंग नहीं होता, यह वे भली-भांति समझते हैं, लेकिन अपराध रोकने या अपराधियों को खत्म करने के लिए प्रशासन को भी सशक्त होना चाहिए। अपराधी कभी भी पूर्व सूचना देकर अपराध नहीं करता बल्कि वह लचर प्रशासन के तहत अपने अनुकूल माहौल का फायदा उठाता है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि आज सिक्किम में बढ़ते अपराध का एकमात्र कारण खराब प्रशासन और सरकार की अक्षमता है।

शर्मा ने कहा कि राज्य में हो रही तमाम आपराधिक घटनाएं इस बात की पुष्टि करती हैं कि सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी और उनकी सरकार बेहद संवेदनहीन होती जा रही है। हाल ही में एक नाबालिग लड़की की दुष्कर्म के बाद हत्या की घटना दिल्ली में हुए निर्भया कांड से कम दर्दनाक नहीं है। ऐसे में राज्यवासी हत्यारे की मृत्युदंड की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। यह राजनीति नहीं है।

उन्होंने आगे कहा, घटना के बाद जहां एक ओर सरकार की बेगुनाही साबित करने के लिए एसकेएम पार्टी प्रेस वार्ता करने लग गई, वहीं दूसरी ओर एसकेएम की सोशल मीडिया टीम वनभोज मनाने चली गई जिसमें सरकारी सलाहकार एवं उच्च राजनीतिक (शेष पृष्ठ ०३ पर)

निकाय चुनाव में बीजेपी को मिलेगी करारी हार : अखिलेश

लखनऊ, 20 अप्रैल (एजेन्सी)। सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक बनकर व्यस्त है और उनका प्रशासनतंत्र अपराधियों के आगे पस्त है। आम जनता निकाय चुनावों में ही भाजपा को करारा सबक सिखाकर वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा की पराजय की पटकथा लिख देगी।

अखिलेश ने कहा कि दिन दहाड़े अपराधिक घटनाएं हो रही है, पर दावा किया जाता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीकठाक है। जनता भी जान गई है कि भाजपा को भ्रामक प्रचार करने में महारत हासिल है। राजधानी लखनऊ में ही जंगलराज के हालात है। कृष्णानगर में बदमाशों ने दिन दहाड़े पिस्तौल की नोक पर एक महिला की चेन लूट ली। कैसरबाग इलाके में व्यापारी से 13 लाख रुपये की लूट हो गई। एक संविदा कर्मी ने नौकरी के नाम पर युवती से वसूली की और दुष्कर्म किया। पारा के बुद्धेश्वर मंदिर पर एक बुजुर्ग की सोने की माला बदमाशों ने लूट ली।

ये घटनाएं तो महज उदाहरण के लिए हैं। प्रदेश में हर दिन लूट, हत्या, छेड़छाड़ और दुष्कर्म की घटनाएं होती हैं। पुलिस ज्यादातर मामलों में पीड़ित की मदद के बजाय अपराधी तत्वों के ही पक्ष में दबाव बनाने का काम करती है। लचर विवेचना और अभियोजन में लापरवाही से तमाम अपराधी छूट जाते हैं। भाजपा राज में कानून व्यवस्था बुरी तरह चौपट है। महिलाएं और बच्चियां असुरक्षित हैं। जनता इस सबसे ऊब चुकी है।

समाजवादी पार्टी ने वाराणसी नगर निगम के महापौर एवं पार्षद चुनाव के लिए पूर्व मंत्री एवं विधायक ओम प्रकाश सिंह को चुनाव प्रभारी नामित किया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की स्वीकृति से प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने इसकी घोषणा की। इसके अलावा भदोही के विधायक जाहिद बेग को मिर्जापुर के छानबे विधानसभा उपचुनाव की संचालन समिति क प्रभारी नामित किया गया है। वहीं पार्टी अध्यक्ष ने एडवोकेट वीरेंद्र को गाजियाबाद का महानगर अध्यक्ष बनाया है।

पार्टी अध्यक्ष की स्वीकृति से नगर पालिका परिषद, इटावा के चुनाव के लिए दस सदस्यीय संचालन समिति का गठन पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ने किया है। समिति में जिला पंचायत अध्यक्ष अंशुल

यादव, पूर्व चेयरमैन पीसीएफ अंकुर यादव, पूर्व प्रत्याशी सर्वेश शाक्य, नगर पालिका परिषद के चेयरमैन फुरकान अहमद, पूर्व प्राचार्य अजन्त सिंह, विधायक भरथना राघवेंद्र गौतम, पूर्व जिलाध्यक्ष गोपाल यादव, बृजमोहन राजपूत, चंदन पाल व इदरीश अंसारी शामिल हैं।

भूमि हस्तांतरण मामले में नहीं मिली रॉबर्ट वाड्रा की कोई भूमिका, आगे की जांच करेगी

चंडीगढ़, 20 अप्रैल (एजेन्सी)। रॉबर्ट वाड्रा और हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ दर्ज मामले में प्राथमिक जांच के दौरान सामने आया है कि राजस्व अधिकारियों को भूमि हस्तांतरण करने की प्रक्रिया में कोई उल्लंघन नहीं किया गया है। इस दौरान हुए लेन-देन से जुड़े रिकॉर्ड की जांच करने में पुलिस जुटी है और एक डीसीपी, दो एसीपी, एक इंस्पेक्टर और एएसआई की विशेष जांच टीम गठित की गई है। आईजी क्राइम ने यह जानकारी हाईकोर्ट में हलफनामे के माध्यम से सौंपी है।

हलफनामा दाखिल करते हुए बताया गया कि तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने 3.5 एकड़ भूमि डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड को सितंबर 2019 में बेची थी। इस प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं पाई गई। वजीराबाद के तहसीलदार ने बताया कि विवादित भूमि अभी डीएलएफ के नाम पर नहीं बल्कि एचएसवीपी के नाम पर है। इस मामले में आगे की जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन किया गया है। विशेष जांच

दल इस मामले में अन्य पहलुओं की जांच करेगा और इस मामले में हुई आगे की प्रगति के बारे में कोर्ट को सूचित किया जाएगा। माननीयों पर लंबित मामलों को लेकर हाईकोर्ट द्वारा लिए गए संज्ञान मामले में यह जानकारी हरियाणा सरकार द्वारा सौंपी गई है।

बिहार की गायिका के साथ बनारस में दुष्कर्म, वीडियो बनाकर ब्लैकमेल, पीड़िता बोली- प्यार के नाम पर धोखा

वाराणसी, 20 अप्रैल (एजेंसी)। बिहार के कैमूर जिले की गायिका को शादी का झांसा देकर वाराणसी के पहड़िया स्थित एक स्टूडियो संचालक ने दुष्कर्म किया। गायिका के गर्भवती होने पर स्टूडियो संचालक ने उसे गर्भपात कराने के लिए कहा। बात न मानने पर जान से मारने की धमकी दी।

प्रकरण को लेकर पीड़िता की शिकायत के आधार पर लालपुर पांडेयपुर थाने में पहड़िया स्थित जानकी वाटिका निवासी सुनील यादव के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया है। पीड़िता के अनुसार, वह अपने गाने की रिकॉर्डिंग के लिए सुनील यादव के पहड़िया स्थित एसआर स्टूडियो में आती थी।

सुनील यादव ने कहा कि वह उससे प्रेम करता है और शादी करना चाहता है। रिकॉर्डिंग के दौरान ही एक दिन सुनील ने अपने स्टूडियो में उसके साथ दुष्कर्म किया और वीडियो भी बना लिया। इसके बाद वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे अपने साथ पत्नी के जैसे रखने लगा, लेकिन शादी नहीं किया।

गायिका ने बताया कि वह डेढ़ माह से गर्भवती है। सुनील ने उससे शादी से इंकार कर दिया है और गर्भपात कराने के लिए कहा है। गर्भपात न कराने पर जान से मारने की धमकी दिया है। इस संबंध में लालपुर पांडेयपुर थाना प्रभारी पंकज कुमार अंबष्ट ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही है।

नई दिल्ली की साइबर थाना पुलिस ने फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाकर युवती को ब्लैकमेल कर संबंध बनाने का दबाव डालने के आरोप में कॉन्वेंट स्कूल के एक शिक्षक को वाराणसी से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान टड़िया, वाराणसी निवासी सुजीत कुमार (27) के रूप में हुई है।

पुलिस ने आरोपी के पास से वारदात में इस्तेमाल मोबाइल व सिमकार्ड बरामद कर लिया है। दरअसल, आरोपी ने युवती की बेहद पर्सनल रिपोर्ट एक दोस्त के जरिये प्राप्त कर ली थी। इसके आधार पर आरोपी युवती से उसकी अश्लील तस्वीरें मांगने के अलावा संबंध बनाने का दबाव डाल रहा था। ऐसा नहीं करने पर आरोपी रिपोर्ट को उसके माता-पिता को शेयर करने के अलावा सोशल मीडिया पर डालने की धमकी दे रहा था। पुलिस के मुताबिक आरोपी बीटेक है और वाराणसी के एक नामी स्कूल में गणित का शिक्षक है।

आजीवन कारावास की सजा पाए दोषी को छूट देने का आदेश रद्द, एक माह में दोषी को समर्पण करने का आदेश

प्रयागराज, 20 अप्रैल (एजेन्सी)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो आपराधिक मामलों में आजीवन कारावास की सजा पाए दोषी को छूट देने के यूपी सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है। यूपी सरकार ने यह आदेश 2019 में दिया था।

कोर्ट ने कहा कि झांसी के रहने वाले दोषी मान सिंह का मामला राज्य सरकार की छूट नीति के अनुसार निषेध नंबर (एक्स) के अंतर्गत आता है। इसलिए वह छूट का हकदार नहीं है।

कोर्ट ने दोषी को तीस दिनों के भीतर आत्मसमर्पण करने और सजा के शेष हिस्से को भुगतने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक कुमार बिड़ला और न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने संजय वर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

यूपी सरकार की 2018 की छूट नीति के तहत निषेध वर्ग के खंड (एक्स) में कहा गया है कि एक ऐसे दोषी की सजा को कम किया जा सकता है जो एक से अधिक आपराधिक मामलों में आजीवन कारावास की सजा का दोषी न हो मौजूदा मामले में अदालत ने कहा, दोषी की सजा को कम नहीं किया जा सकता है। उसका मामला खंड (एक्स) के तहत आता है। क्योंकि, उसे दो मामलों में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इनमें से एक सजा वर्ष 1995 में दी गई थी।

कोर्ट ने देखा कि मान सिंह का 26 अन्य मामलों का आपराधिक इतिहास भी है, जिसे राज्यपाल के ध्यान में नहीं लाया गया था। उल्लेखनीय है कि राज्यपाल के पास संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत दोषी को क्षमा करने, सजा को कम करने और रिहा करने की शक्ति है।

अदालत के समक्ष याची के वकील ने तर्क दिया कि दोषी का 27 मामलों का आपराधिक इतिहास था, जिसे छूट देते समय ध्यान नहीं दिया गया था।

यह भी प्रस्तुत किया गया कि सरकार की 2018 की छूट नीति के अनुसार अपराधी को पहले उम्रकैद की सजा दी गई है, जिससे वह छूट के लिए अयोग्य हो जाता है।

दूसरी ओर, राज्य सरकार ने अपने आदेश को सही ठहराते हुए एक हलफनामा दायर किया। जिसमें यह तर्क दिया गया कि संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत दोषी व्यक्तियों की समय से पहले रिहाई के लिए राज्यपाल के पास छूट देने की शक्ति है और आक्षेपित आदेश वैध रूप से पारित किया गया था।

यह तर्क दिया गया था कि राज्य की छूट नीति के अनुसार उसने 12 वर्ष, दो महीने बिना किसी छूट सहित 14 वर्ष 6 महीने, 10 दिन की सजा काट ली है। मेडिकल बोर्ड की राय थी कि दोषी को कांजेस्टिव हर्ट फेल्योर की शिकायत है, इस वजह से दोषी छूट प्राप्ति का हकदार है।

राज्य ने अपने हलफनामे में माना था कि दोषी का आपराधिक इतिहास है। इस पृष्ठभूमि में न्यायालय ने शुरुआत में ही कहा कि राष्ट्रपति या राज्यपाल की ओर से क्षमादान की शक्ति का प्रयोग या गैर प्रयोग जैसा भी मामला हो, न्यायिक पुनर्विचार से मुक्त नहीं है।

सुवेंदु अधिकारी की सीएम ममता को खुली चुनौती, बोले- उनको हराने में नाकाम रहा तो छोड़ दूंगा राजनीति

कोलकाता, 20 अप्रैल (एजेन्सी)। भाजपा के वरिष्ठ नेता सुवेंदु अधिकारी ने बृहस्पतिवार को कहा कि अगर वह ममता बनर्जी को लोकतांत्रिक तरीके से हराने में नाकाम रहे तो वह राजनीति छोड़ देंगे। इससे पहले पश्चिम बंगाल में नेता विपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने दावा किया था कि टीएमसी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म किए जाने के बाद ममता बनर्जी ने अमित शाह को फोन किया था।

हालांकि टीएमसी ने इस बयान को खारिज कर दिया था और टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सुवेंदु को अदालत में घसीटने की बात की थी। वहीं अब एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान अधिकारी ने कहा कि अगर मैं ममता बनर्जी को लोकतांत्रिक तरीके से हराने और उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री बनाने में विफल रहा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा।

टीएमसी ने बुधवार को एक पत्र के माध्यम से अधिकारी को अपने झूठे और अपमानजनक दावों को वापस लेने के लिए कहा और उन्हें कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि मुझे टीएमसी से एक पत्र मिला है। मैं शुक्रवार को इसका जवाब दूंगा। सुरक्षा प्रोटोकॉल के कारण, मुझे मुख्यमंत्री के कार्यालय से फोन कॉल का विवरण नहीं मिल सकता है। यह आरटीआई के दायरे से बाहर है।

भाजपा नेता ने कहा कि अगर वे अदालत जाते हैं, तो मैं इस मामले में बीएसएनएल और ट्राई को पक्षकार बनाऊंगा, जो मुख्यमंत्री के लैंडलाइन से किए गए कॉल के रिकॉर्ड को निकाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि वह हमेशा झूठ बोलते हैं।

वहीं टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा सुवेंदु की आदत झूठ बोलने की है। यह पहली बार नहीं है, पहले भी उन्होंने ऐसा किया है। उन्हें साबित करने दें कि उन्होंने फोन कॉल के बारे में जो कहा वह सही था, और मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा है तो वह खुद पद छोड़ देंगी। वो यह साबित करके दिखाएं नहीं तो उनको अदालत में घसीटा जाएगा।

बागियों ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन, भूपेंद्र चौधरी बोले- हर हाल में मनाकर नामांकन वापस कराएं

लखनऊ, 20 अप्रैल (एजेन्सी)। निकाय चुनाव में किसी भी प्रकार की जोखिम से बचने के लिए भाजपा ने अब बागियों को मनाने पर फोकस कर दिया है। निकाय चुनाव के पहले चरण के नाम वापसी का बृहस्पतिवार को अंतिम दिन हैं। इसलिए भाजपा ने टिकट न मिलने से नाराज होकर निर्दलीय नामांकन करने वाले बागियों को मनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। बुधवार को चुनावी तैयारियों को लेकर हुई वर्चुअल बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी व प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने बागियों को हर हाल में मनाकर नामांकन वापस कराने के निर्देश दिया है।

बैठक में शामिल पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों, क्षेत्रीय अध्यक्षों, जिला प्रभारी व जिलाध्यक्षों व निकाय चुनाव से जुड़े पार्टी नेताओं को कहा गया है कि गया है कि बागियों को मनाने के लिए अगर किसी बड़े या प्रभावशाली नेताओं के मदद की जरूरत हो तो तत्काल प्रदेश मुख्यालय को सूचना दिया जाए। वहीं, चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए कार्यकर्ताओं को घर-घर संपर्क व संवाद करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रथम चरण के लिए नामांकन का कार्य पूरा हो चुका है, इसलिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लोक कल्याण के लिए किए गए कार्यों की चर्चा घर-घर पहुंचाने का काम करना है। उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव की तरह ही पार्टी कार्यकर्ता निकाय चुनाव में भी पूरी ताकत से जुटें। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के परिश्रम से भाजपा निकाय चुनाव में भी ऐतिहासिक सफलता हासिल करेगी।

वहीं, महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह ने कहा कि प्रत्येक नगर निकायों में माहौल बनाने के लिए युवा मोर्चा द्वारा युवा सम्मेलन और महिला मोर्चा द्वारा महिला सम्मेलन कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि जहां भी प्रभावी मतदाता सम्मेलन शेष बचे हैं, उसे भी चुनाव प्रचार के दौरान ही संपन्न करा लिए जाएं। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता मोदी-योगी सरकार की उपलब्धियों को लेकर घर-घर संपर्क अभियान शुरू करें।

राहुल की अपील खारिज होने पर महबूबा बोलीं- 'काला दिन'

अनंतनाग, 20 अप्रैल (एजेन्सी)। गुजरात की एक अदालत द्वारा मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अपील खारिज कर दिए जाने के बाद पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधा है।

गुजरात की एक अदालत द्वारा मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अपील खारिज कर दिए जाने के बाद पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधते हुए कहा कि यह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक 'काला दिन' है।

उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं को परेशान किया जा रहा है और वे या तो जेल में हैं या उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। महबूबा ने श्रीनगर से करीब 55 किलोमीटर दूर यहां संवाददाताओं से कहा, लोकतंत्र की जननी होने पर गर्व करने वाले देश के लोकतांत्रिक इतिहास में आज काला दिन है। राहुल गांधी के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है, वह दर्शाता है कि भाजपा लोकतंत्र को समाप्त करना चाहता है। वे एकदलीय प्रणाली स्थापित करना चाहते हैं - संविधान को दरकिनार करके भाजपा राष्ट्र।

पीडीपी नेता सूरत की एक अदालत द्वारा एक आपराधिक मानहानि मामले में दोषसिद्धि के खिलाफ राहुल गांधी की अपील खारिज कर दिए जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहीं थीं। जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, 'न्यायपालिका लोगों की अंतिम उम्मीद है लेकिन इसकी हालिया भूमिका से सवाल पैदा होते हैं। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 से जुड़ी याचिकाओं को देखिए, वे कई साल से बिना सुनवाई के लंबित हैं।

उन्होंने कहा, 'बिल्कीस बानो का मामला लंबित है, पर राहुल गांधी के मामले में तेजी लाई जा रही है।' महबूबा ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी एक विश्वसनीय चेहरे के रूप में उभरे हैं और ऐसा लगता है कि भाजपा राहुल गांधी की लोकप्रियता से 'डर' गई है। उन्होंने कहा, 'मुझे भरोसा है कि लोग वेस्ट इंडिया कंपनी के कुशासन के खिलाफ उसी प्रकार उठ खड़े होंगे जिस प्रकार वे 1947 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ खड़े हुए थे।

पंचायत चुनाव से पहले टीएमसी ने किया नए जनसंपर्क अभियान का एलान, 3500 किलोमीटर की होगी यात्रा

कोलकाता, 20 अप्रैल (एजेन्सी)। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने पश्चिम बंगाल में आगामी पंचायत चुनावों को ध्यान में रखते हुए गुरुवार को एक नए जनसंपर्क कार्यक्रम का एलान किया। यह कार्यक्रम अन्य लक्ष्यों के अलावा मतदाताओं को उम्मीदवारों को चुनने के लिए सशक्त बनाने का प्रयास करेगा। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 'तृणमूल नबाजोवार' (तृणमूल में नई लहर) नाम का यह अभियान 25 अप्रैल से शुरू होगा और 60 दिनों तक चलेगा, जिस दौरान वह राज्य के उत्तरी हिस्से से दक्षिणी हिस्से तक 3500 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे।

उन्होंने कहा, 'यह कार्यक्रम जनता तक पहुंचेगा और उन्हें लोगों को पंचायत स्तर के लिए त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली के लिए उम्मीदवार चुनने के लिए सशक्त बनाएगा। पार्टी द्वारा एक गुप्त मतदान प्रणाली आयोजित की जाएगी, जहां ग्रामीण प्रतिक्रिया प्रदान कर सकते हैं कि वे किसे अपने उम्मीदवार के रूप में चाहते हैं। पार्टी उस व्यक्ति को नामित करेगी।'

पार्टी में नंबर दो माने जाने वाले अभिषेक बनर्जी ने कहा, 'कार्यक्रम का उद्देश्य लोकतांत्रिक और विकेंद्रीकृत प्रक्रिया के जरिए जन प्रतिनिधियों के सही समूह की पहचान करके लोगों की राय लेकर जमीनी स्तर पर प्रगति और विकास की एक नई लहर की शुरुआत करना है।'

जनसंपर्क कार्यक्रम ऐसे समय में आया है जब पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी भ्रष्टाचार के विभिन्न आरोपों का सामना कर रही है और उसके कई नेताओं को सीबीआई और ईडी ने गिरफ्तार किया है।

'तृणमूल नबाजोवार' का विवरण देते हुए बनर्जी ने कहा कि दो महीने के कार्यक्रम के दौरान वह 3,500 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे और पूरे पश्चिम बंगाल में 250 से अधिक रैलियों को संबोधित करेंगे।

उन्होंने कहा, 'मैं हर दिन तीन-चार रैलियों को संबोधित करूंगा। कार्यक्रम कूच बिहार से शुरू होगा और दक्षिण 24 परगना के काकद्वीप में समाप्त होगा। मैं इस पूरे दो महीने के दौरान सड़कों पर रहूंगा। मैं लोगों से मिलूंगा, सामुदायिक रात्रिभोज में भाग लूंगा, रैलियां करूंगा।' अभियान को दो भागों में विभाजित किया गया है- 'जन संजोग यात्रा' (पब्लिक आउटरीच कैंपेन) और 'ग्राम बंगलार मोटामोट' (ग्रामीण बंगाल की राय)।

उन्होंने कहा, 'ग्राम बंगलार मोटामोट के तहत पंचायत चुनावों के लिए उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने के लिए अपनी तरह का पहला जनमत संग्रह कराया जाएगा। लोग त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए सही उम्मीदवार की सिफारिश करने के लिए गुप्त मतदान में भाग ले सकेंगे। तृणमूल कांग्रेस के दो बार के सांसद ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के साथ बराबरी करने की खबरों को खारिज करते हुए कहा कि अगर यह कार्यक्रम नगर निगम क्षेत्रों सहित पूरे राज्य को कवर करने के लिए पैदल आयोजित किया गया होता, तो इसमें कम से कम दो साल लग जाते।

यह पूछे जाने पर कि अगर स्थानीय लोग विपक्षी पार्टी के किसी कार्यकर्ता को अपने वांछित उम्मीदवार के रूप में वोट देते हैं तो पार्टी क्या करेगी, उन्होंने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से उस व्यक्ति से बात करेंगे ताकि उसे टीएमसी के टिकट पर लड़ने के लिए राजी किया जा सके। उन्होंने कहा, 'अगर वह हमारे उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने के लिए सहमत होते हैं, तो यह ठीक होगा।' पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे ने कहा, 'अगर ऐसा नहीं होता है तो हम उम्मीदवार चुनने से पहले फिर से स्थानीय लोगों की राय लेंगे।'

पिछले कुछ महीनों से बनर्जी कहते रहे हैं कि लोग पंचायत चुनावों के लिए, तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों का फैसला करेंगे। यह पूछे जाने पर कि क्या इस अभियान का उद्देश्य खराब तत्वों को बाहर निकालना है, उन्होंने कहा, 'मैं यह नहीं कह सकता कि कुछ स्तरों पर भ्रष्टाचार का कोई उदाहरण नहीं है। यह अभियान केवल भ्रष्ट तत्वों को बाहर निकालने के लिए लोगों को सशक्त करेगा।' वर्तमान में राज्य की सभी जिला परिषदों और अधिकांश ग्राम पंचायतों पर टीएमसी का नियंत्रण है।

राज्य में 2018 के पंचायत चुनावों के दौरान विभिन्न हिस्सों से व्यापक हिंसा की सूचना मिली थी। ऐसे आरोप थे कि विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ता टीएमसी नेताओं की धमकियों के कारण नामांकन पत्र दाखिल नहीं कर सके। 2019 के लोकसभा चुनावों में टीएमसी की सीटों की संख्या 34 से घटकर 22 हो गई और विपक्षी भाजपा की सीटों की संख्या राज्य में दो से बढ़कर 18 हो गई।

तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि पार्टी शांतिपूर्ण चुनाव चाहती है और अगर विपक्ष नामांकन दाखिल नहीं कर पाने की शिकायत करता है तो वह व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके उम्मीदवार ऐसा करने में सक्षम हो सकें'। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से अधिकांश में ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्र पंचायतों द्वारा प्रशासित हैं, 2024 में संसदीय चुनावों में प्रतिद्वंद्वियों पर बढ़त बनाने के लिए राजनीतिक दलों के लिए ग्रामीण निकायों का पूर्ण नियंत्रण आवश्यक है।

पिछले चार वर्षों में टीएमसी द्वारा शुरू किए गए राजनीतिक परामर्श समूह- आई-पीएसी द्वारा परिकल्पित यह पांचवां जनसंपर्क अभियान है। उनमें से पहला 'दीदी के बोलो' था, जो 2019 के लोकसभा चुनावों में हार के महीनों बाद शुरू हुआ था। आखिरी अभियान इस साल जनवरी में किया गया था, जिसका नाम 'दीदीर सुरक्षा कवच' (दीदी का सुरक्षा कवच) था। पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी को उनके अनुयायी 'दीदी' (बड़ी बहन) कहते हैं।

आधुनिक समस्याओं का समाधान पहले ही दे गए बुद्ध : पीएम मोदी

नई दिल्ली, 20 अप्रैल (एजेन्सी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वैश्विक बौद्ध समिट के उद्घाटन सत्र का उद्घाटन किया। मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि दुनिया की हर समस्या का समाधान भगवान बुद्ध पहले ही दे गए।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यूक्रेन-रूस युद्ध, मौजूदा वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चिंताओं को इस सदी की सबसे बड़ी चुनौती करार देते हुए, कहा कि आज समय की मांग है कि प्रत्येक राष्ट्र की प्राथमिकता अपने देश के हित के साथ ही विश्व हित भी हो।

राजधानी स्थित अशोक होटल में आयोजित पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा, आज दुनिया जिस युद्ध और अशांति से पीड़ित है, उसका समाधान बुद्ध के उपदेशों में है।

उन्होंने कहा, हमें विश्व को सुखी बनाना है तो स्व से निकलकर संसार, संकुचित सोच को त्यागकर, समग्रता का यह बुद्ध मंत्र ही एकमात्र रास्ता है।

मोदी ने कहा कि सभी को अपने आस-पास गरीबी से जूझ रहे लोगों के बारे में और साथ ही संसाधनों के अभाव में फंसे देशों के बारे में सोचना ही होगा।

उन्होंने कहा, एक बेहतर और स्थिर विश्व की स्थापना के लिए यही एक मार्ग है। आज यह समय की मांग है कि हर व्यक्ति की, हर राष्ट्र की प्राथमिकता अपने देश के हित के साथ ही विश्व हित भी हो।

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बात सर्व स्वीकार्य है कि आज का यह समय इस सदी का सबसे चुनौतीपूर्ण समय है।

उन्होंने कहा, आज एक ओर महीनों से दो देशों में युद्ध चल रहा है तो वहीं दुनिया आर्थिक अस्थिरता से भी गुजर रही है। आतंकवाद और मज़हबी उन्माद जैसे खतरे मानवता की आत्मा पर प्रहार कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौती पूरी मानवता के अस्तित्व पर आफत बनकर मंडरा रही है। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। पारिस्थितिकीय तंत्र नष्ट हो रहे हैं। प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। लेकिन इन सबके बीच हमारे आप जैसे करोड़ों लोग भी हैं जिन्हें बुद्ध में आस्था है और जीव मात्र के कल्याण में विश्वास है।

प्रधानमंत्री ने इस उम्मीद को इस धरती की सबसे बड़ी ताकत करार दिया और कहा कि जब यह ताकत एकजुट होगी तो बुद्ध का धम्म विश्व की धारणा बन जाएगा और बुद्ध का बोध मानवता का विश्वास बन जाएगा।

उन्होंने कहा कि आधुनिक विश्व की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान सैंकड़ों वर्ष पहले दिए गए बुद्ध के उपदेशों में न हो। उन्होंने कहा कि आज दुनिया जिस युद्ध और अशांति से पीड़ित है, उसका समाधान बुद्ध ने सदियों पहले दे दिया था।

इस दो दिवसीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी संस्कृति मंत्रालय अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से कर रहा है। शिखर सम्मेलन का विषय समकालीन चुनौतियों पर प्रतिक्रिया : अभ्यास के लिए दर्शन है। यह वैश्विक शिखर सम्मेलन बौद्ध धर्म में भारत के महत्व और अहमियत को चिन्हित करेगा।

शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य शाक्यमुनि बुद्ध की शिक्षाओं पर गौर करना है जो सदियों से बुद्ध धम्म के अभ्यास से लगातार समृद्ध होती रही हैं।

समलैंगिक लोगों की शादी में आ सकता है स्थायित्व : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 20 अप्रैल (एजेन्सी)। समलिंगी शादी को मान्यता की याचिका पर सुनवाई के दौरान सीजेआई चंद्रचूड़ ने अहम टिप्पणी दी है। उन्होंने कहा कि समलैंगिक संबंध एक बार का रिश्ता नहीं, अब ये रिश्ते हमेशा के लिए टिके रहने वाले हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि भारत को संवैधानिक और सामाजिक रूप से देखते हुए, हम पहले से ही उस मध्यवर्ती चरण में पहुंच गए हैं, जहां समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, कोई यह सोच सकता है कि समान लिंग के लोग स्थिर विवाह जैसे रिश्ते में स्थिर हों। प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि पिछले 69 वर्षों में, कानून वास्तव में विकसित हुआ है।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, जब आप समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करते हैं, तो आप यह भी महसूस करते हैं कि ये एकबारगी संबंध नहीं हैं, ये स्थिर संबंध भी हैं। समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करके, हमने न केवल समान लिंग के सहमति देने वाले वयस्कों के बीच संबंधों को मान्यता दी है, हमने अप्रत्यक्ष रूप से भी मान्यता दी है। इसलिए, तथ्य यह है कि जो लोग समान लिंग के हैं वे स्थिर संबंधों में होंगे।,

न्यायमूर्ति एसके कौल, एस रवींद्र भट, हेमा कोहली और पीएस नरसिम्हा की खंडपीठ ने कहा कि 1954 (विशेष विवाह अधिनियम) में कानून का उद्देश्य उन लोगों को शामिल करना था, जो एक वैवाहिक संबंध द्वारा शासित होंगे। उनके व्यक्तिगत कानूनों के अलावा। पीठ ने समलैंगिक विवाहों के लिए कानूनी मंजूरी की मांग करने वाले कुछ याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी से कहा कि कानून निश्चित रूप से व्यापक रूप से सक्षम है, आपके अनुसार समान लिंग के स्थिर संबंधों को भी ध्यान में रखा जा सकता है।

सिंघवी ने कहा, मैं इसे बहुत स्पष्ट रूप से रखता हूं। जब आपने कानून बनाया, संसद में बहस में, आपके दिमाग में समलैंगिकों का विचार नहीं हो सकता है। आपने उन्हें नहीं माना होगा। सीजेआई ने जवाब दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।

पीठ ने कहा कि आपका सिद्धांत यह है कि जब 1954 में कानून बनाया गया था, तो कानून का उद्देश्य उन लोगों के लिए विवाह का एक रूप प्रदान करना था, जो अपने व्यक्तिगत कानूनों से पीछे नहीं हट रहे हैं।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि संस्थागत क्षमता के दृष्टिकोण से, हमें खुद से पूछना होगा कि क्या हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो मौलिक रूप से कानून की योजना के विपरीत है, या कानून की संपूर्णता को फिर से लिख रहे हैं, अदालत नीतिगत विकल्प बनाएगी, जो कि विधायिका को बनाना है।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, जब तक हम न्यायिक प्रक्रिया से नीति को विभाजित करने वाली उस रेखा से नहीं जुड़ते हैं, तब तक आप इसके दायरे में हैं।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि संवैधानिक और सामाजिक रूप से भी भारत को देखते हुए,हम पहले से ही मध्यवर्ती चरण में पहुंच गए हैं। मध्यवर्ती चरण में यह माना जाता है कि समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करने का कार्य इस बात पर विचार करता है कि ऐसे लोगों के रिश्ते स्थिर विवाह जैसे होंगे। उन्होंने कहा, जिस क्षण हमने कहा कि यह अब धारा 377 के तहत अपराध नहीं है, इसलिए हम अनिवार्य रूप से विचार करते हैं कि आप दो व्यक्तियों के बीच एक स्थिर विवाह जैसा संबंध बना सकते हैं।

खंडपीठ ने कहा कि यह न केवल एक शारीरिक संबंध, बल्कि कुछ और अधिक स्थिर भावनात्मक संबंध है, जो अब संवैधानिक व्याख्या की घटना है। पीठ ने मामले की सुनवाई जारी रखी है।

माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता की तलाश तेज, चौतरफ हो रही छापेमारी

प्रयागराज, 20 अप्रैल (एजेन्सी)। माफिया अतीक अहमद की मोस्टवांटेड पत्नी शाइस्ता परवीन को खोजने के लिए पुलिस की कई टीमें लगी हैं, जो जगह-जगह छापेमारी कर रही हैं।

पुलिस के सूत्र बताते हैं कि हर रोज पुलिस को शाइस्ता के बारे में नए सुराग मिलते हैं, लेकिन वह गायब हो जा रही है। पुलिस की पकड़ से वह अभी दूर है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस प्रयागराज के साथ कौशांबी जनपद में जगह-जगह छापा मार रही है। कई घरों में खोजबीन के साथ गंगा और यमुना के कछारी इलाके में ड्रोन कैमरे के माध्यम से अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि अभी वह पकड़ से दूर है।

कई राज्यों, शहरों में छापामारी के बाद एक बार फिर प्रयागराज और कौशाम्बी के कई गांवों में तलाश शुरू हुई। पुलिस को सुराग मिली थी कि अतीक की पत्नी कौशाम्बी के कछारी इलाकों में छिपी हो सकती है। इसके बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। रिहायशी इलाकों के साथ खंडहर, जंगल और नदी के किनारे पुलिस टीमें छापामारी को पहुंची।

स्थानीय लोगों के मुताबिक अतीक की अधिकतर रिश्तेदारियां खुल्दाबाद, कौशांबी, कोखराज और संदीपन घाट के गांवों में हैं। पुलिस को भनक लगी की वह गंगा के कछार में छिपी है। पुलिस ने कौशांबी के खालसा, उजैहिनी समेत कई गांवों में छापेमारी की, लेकिन शाइस्ता का पता नहीं चला।

प्रयागराज में कई मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं, जहां अतीक के परिवार का खासा दबदबा माना जाता है। साथ ही गंगा पार और यमुनापार के इलाकों में भी उसके तमाम जानने वाले हैं। माना जा रहा है कि वह जिले में ही कहीं छिपी है और लगातार ठिकाने बदल रही है।

सूत्र बताते हैं कि उमेश हत्याकांड में शामिल जो लोग भी अब तक पुलिस की गिरफ्त में आए हैं, वे मारे ही गए हैं। ऐसे में शाइस्ता पुलिस पर भी विश्वास नहीं कर पा रही है। पति अतीक और देवर अशरफ की हत्या के बाद परिवार में वो ही सबसे बड़ी सदस्य है। ऐसे में चार बेटों को संभालने की जिम्मेदारी भी उस पर है। हो सकता है इसीलिए शाइस्ता कोई खतरा मोल न लेना चाहती हो। यही वजह है कि शाइस्ता बेटे असद और पति अतीक के जनाजे में भी नहीं पहुंची।

संभावना जताई जा रही है कि कुछ सफेदपोश लोगों ने अपना राज खुलने के डर से अतीक की हत्या करवाई है। ऐसे में शाइस्ता को भी डर है कि वह इस वक्त अगर सरेंडर करती है, तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। ऐसे में शाइस्ता सरेंडर के लिए सही समय का इंतजार कर रही है।

ज्ञात हो कि विधायक राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की 24 फरवरी को हत्या के बाद से ही माफिया डॉन अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन फरार चल रही है। परवीन के ऊपर अब 50 हजार का इनाम घोषित है। उसकी खोजबीन में पुलिस और एसटीएफ की कई टीमें लगी है, लेकिन उसका कहीं सुराग नहीं लग सका है। शाइस्ता अपने बेटे असद के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद भी सामने नहीं आई। शौहर अतीक और देवर की हत्या हो गई, लेकिन वह जनाजे में नहीं पहुंची।

राष्ट्रपति मुर्मू ने ऐतिहासिक भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान का किया दौरा

शिमला, 20 अप्रैल (एजेन्सी)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान (इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज) के ऐतिहासिक भवन का दौरा किया। वह करीब 40 मिनट संस्थान में रुकी रहीं। यहां पर उन्होंने अंदर रखे ऐतिहासिक वस्तुओं, फोटो गैलरी, आधुनिक सुविधाओं से लैस पुस्तकालय और निदेशक के कार्यालय का दौरा किया। राष्ट्रपति ने भवन में बने वायसरॉय के कमरों को भी देखा, जहां वह रहा करते थे। इस दौरान उन्होंने इसकी गैलरी से बाहर निकल कर आसपास के प्राकृतिक सौंदर्य को निहारा।

राष्ट्रपति के आने पर राज्यपाल शिव प्रताप सिंह, संस्थान अध्यक्ष प्रो. शशि प्रभा कुमार, उपाध्यक्ष शैलेंद्र राज मेहता, संस्थान के निदेशक प्रो. नागेश्वर रॉव सचिव सुब्रत कुमार प्रधान ने स्वागत किया। राष्ट्रपति ने परिसर में यहां के अध्येताओं, सह अध्येताओं और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सामूहिक चित्र भी खिचवाया। इसके बाद उन्होंने भवन के अंदर तीन फोटो गैलरी का अवलोकन किया। इस दौरान निदेशक और संस्थान के अधिकारियों ने उन्हें इस ऐतिहासिक भवन और इसमें संजोकर रखी ऐतिहासिक घटनाओं की फोटो और वस्तुओं की विस्तार से जानकारी दी। इसमें वह टेबल भी शामिल था, जिस पर बैठकर 25 जून 1945 को शिमला कांफ्रेंस हुई थी। यह भारत-पाक विभाजन को टालने का अंतिम प्रयास था।

राष्ट्रपति ने संस्थान का दौरा पूरा करने के बाद आगंतुक पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए और लिखा - भारत के अग्रणी शोध संस्थान, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, जो मानविकी, समाज शास्त्र और प्राकृतिक विज्ञानों जैसे विषयों पर उच्च गुणवत्तायुक्त अकादमिक शोध को बढ़ावा दे रहा है। मैं यहां आ कर बहुत प्रसन्न हूं। मेरे पूर्व समकक्ष व प्रसिद्ध विद्वान डॉ. राधाकृष्णन द्वारा स्थापित यह संस्थान, शोध और वैचारिक आदान-प्रदान के द्वारा रचनात्मक वैचारिक प्रवाह व उन्मुक्त शोध को प्रोत्साहित करता है। मैं सभी शोधार्थियों, अधिकारियों व कर्मचारियों को संस्थान के उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती हूं।

श्रीनगर में की तैयारियां जोरों पर, बाजारों में त्योहार का उत्साह

श्रीनगर, 20 अप्रैल (एजेन्सी)। जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर शहर में गुरुवार को ईद की खरीदारी जोरों पर चल रही है। बड़ी संख्या में मटन, पोल्ट्री, बेकरी, होजरी और पटाखों की दुकानों पर खरीददारों की भीड़ देखी गई।

खरीददारों की कतारें शहर में मटन की दुकानों पर जमा हो गई।

प्रशासन द्वारा तय की गई दरें न तो बेचने वालों को परेशान करती दिख रही हैं और न ही खरीददारों को।

लोग मटन, पोल्ट्री, बेकरी और अन्य जरूरी सामान खरीदने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। खरीदार अधिक सामान खरीदने के लिए उमड़ रहे हैं। ईद-उल-फितर पर सब्जियां, मटन, पोल्ट्री, बेकरी और होजरी आइटम की सबसे अधिक मांग होती है क्योंकि पवित्र त्योहार रमजान के उपवास के महीने के बाद आता है।

बच्चों को कपड़े और पटाखे खरीदने के लिए ले जाने वाले माता-पिता शहर में एक आम दृश्य हैं। वाहनों की भारी भीड़ के कारण सभी प्रमुख और छोटे यातायात मार्ग पर भारी ट्रैफिक है।

दर्जनों जगहों पर अस्थायी बेकरी की दुकानें खुल गई हैं, जहां विक्रेताओं ने घाटी के विभिन्न जिला मुख्यालयों में अपना माल फैलाया है।

मटन विक्रेता खुलेआम 650 से 700 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से मटन बेच रहे हैं जबकि आधिकारिक तौर पर निर्धारित दर 535 रुपये प्रति किलोग्राम है।

दक्षिण कश्मीर के ग्रामीण इलाकों में हिंसा की छिटपुट घटनाओं के बावजूद कश्मीर में सभी लोग शांति से ईद का त्योहार मनाना चाहते हैं।

परंपरागत रूप से, सुबह अलग-अलग ईदगाहों और मस्जिदों में ईद की नमाज अदा करने के बाद, मुसलमान एक-दूसरे को बधाई देते हैं और दोपहर में अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं।

ईद का दोपहर का भोजन एक पारिवारिक दावत होता है जिसके लिए पूरा परिवार प्रार्थना और तपस्या के महीने के अंत के बाद तत्पर रहता है।

नए कपड़े पहनना एक परंपरा है जो स्थानीय मुसलमानों द्वारा देखी जाती है और ईद की नमाज के लिए लाइन में खड़े हजारों नमाजी रंग और भक्ति का नजारा पेश करते हैं।

सिक्किम में बढ़ रहे ....

नेता मौजूद रहे। यह उनकी असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। एसडीएफ प्रवक्ता ने कहा कि सिक्किम का समाज आज अस्तित्व के सवाल से जूझ रहा है। लड़कियों का शोषण और हत्या, उनके गायब होने की खबरें, हिंसक गतिविधियां आदि बढ़ रही हैं। ऐसे में सरकार को कानून-व्यवस्था एवं प्रशासन की मजबूत हेतु विचार करना चाहिए।

राज्य स्तर पर कुछ नौकरशाहों के पास राजनेताओं से ज्यादा ताकत, आत्ममंथन की जरूरत : धनखड़

नई दिल्ली, 20 अप्रैल (एजेन्सी)। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को कहा कि राज्य स्तर पर कुछ नौकरशाहों के पास राजनेताओं की तुलना में अधिक शक्ति है। उन्होंने आत्मनिरीक्षण और उनकी काउंसलिंग करने का आह्वान किया ताकि सिविल सेवा को लेकर जो लोगों का विश्वास है उसके अनुरूप वे काम कर सकें। सिविल सेवा के अधिकारियों को संबोधित करते हुए धनखड़ ने कहा कि देश के कुछ हिस्सों में राजनीतिक आकाओं की मिलीभगत, संघीय ढांचे पर दबाव और पारदर्शिता एवं जवाबदेही को नुकसान पहुंचाने के कारण 'भारत के मजबूत ढांचे' को कमजोर किया जा रहा है।

उपराष्ट्रपति धनखड़ ने 16वें सिविल सेवा दिवस के दो दिवसीय समारोह के उद्घाटन के मौके पर कहा कि राज्य स्तर पर कुछ नौकरशाह राजनेताओं के लिए एक वास्तविक चुनौती बन रहे हैं। उनके पास अधिक शक्ति है जिससे कोई भी राजनेता ईर्ष्या कर सकता है। इस मामले में आत्मनिरीक्षण और उनकी काउंसलिंग करने की आवश्यकता है ताकि उनकी सेवा लोगों के उस विश्वास के अनुरूप बनी रहे, जिसका प्रतिष्ठा के साथ दशकों से पालन किया गया है।

उन्होंने कहा कि ये महत्वपूर्ण मुद्दे आपस में उलझने के बजाय समाधान की मांग करते हैं। उन्होंने कहा, अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 और संबंधित कानूनी व्यवस्था का ईमानदारी से पालन करना वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। उन्होंने नियमों के एक प्रावधान का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया है एक सिविल सेवक के लिए यह अनिवार्य है कि जब वह अपने वरिष्ठ अधिकारी से मौखिक निर्देश प्राप्त करता है, उसके बाद जल्द से जल्द लिखित में इसकी पुष्टि करेगा। धनखड़ ने कहा कि कुछ मामलों में इसका उल्लंघन देखा गया है।

उपराष्ट्रपति ने कहा, यह एक संवैधानिक अनिवार्यता है कि केंद्र और राज्यों के प्रशासन में एकरूपता होनी चाहिए ताकि संघवाद सहकारी संघवाद में विकसित हो सके जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल्पना की थी। उन्होंने कहा, मुद्दों का हल करने की तत्काल आवश्यकता है ताकि सिविल सेवा की प्रभावकारिता और उदात्तता खो न जाए। धनखड़ ने कहा कि नौकरशाही स्वाभाविक रूप से विधायिका, न्यायपालिका और राजनीतिक कार्यपालिका के हस्तक्षेप से ग्रस्त है। उन्होंने कहा, इन संस्थानों से सद्भाव में कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। वे टकराव में नहीं आ सकते। वे शिकायतकर्ता मोड में नहीं हो सकते। उन्हें सहयोगी रूप में रहना होगा ... इसके लिए हम सभी को काम करना चाहिए। यदि हमारे लोकतंत्र को फलते-फूलते और बनाए रखना है तो शक्तियों के बंटवारे के सिद्धांत का पालन करना होगा

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि 'संगठनों से खतरे निकल रहे हैं', जिसमें कुछ विदेशी विश्वविद्यालय देश की सभ्यता लोकाचार को ध्वस्त करने और इसके विकास को प्रभावित करने के लिए विध्वंसक भारत विरोधी गतिविधियों के केंद्र के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत में तथाकथित अभिजात वर्ग के छिपे हुए एजेंडे में परेशान करने वाली अंतर्दृष्टि खतरनाक है और दुर्भाग्य से यह हमारे संवैधानिक संस्थान के कामकाज में दिखाई दे रहा है।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह संसद की जिम्मेदारी है कि वह आंतरिक या बाहरी किसी भी प्रकार के खतरों से भारत की राष्ट्रीय संप्रभुता और सांस्कृतिक अखंडता की रक्षा करे। 16वें सिविल सेवा दिवस के उद्घाटन समारोह में धनखड़ ने कहा कि अभूतपूर्व विकास और वैभव की राह पर चल रहे हमारे लोकतंत्र को जरूरत है कि उसके पंख - विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका सुचारू रूप से ऊपर की उड़ान के लिए मिलकर काम करें। हम सभी को यह सुनिश्चित करना चाहिए।

उपराष्ट्रपति ने कहा, हमारी सभ्यता के लोकाचार को ध्वस्त करने और हमारे विकास को प्रभावित करने के लिए विध्वंसक भारत विरोधी गतिविधियों के केंद्र के रूप में काम करने वाले कुछ विदेशी विश्वविद्यालयों सहित, भीतर और बाहरी संगठनों से खतरे निकल रहे हैं। उन्होंने कहा कि संसद केवल अकेले 'कानून की प्रभारी' है और इसे लागू करने में सक्षम है।

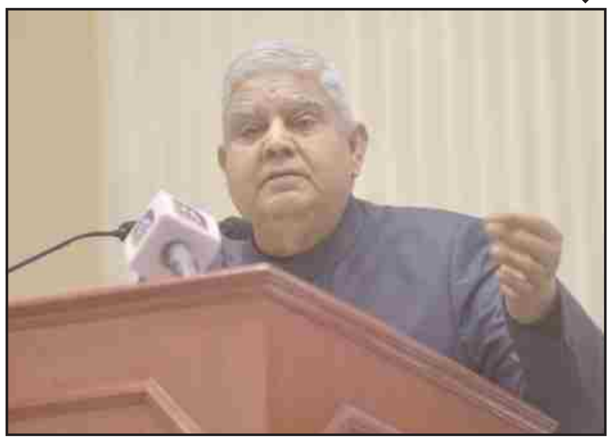

कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर परोक्ष रूप से हमला करते हुए धनखड़ ने कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो भारत के अभूतपूर्व विकास और फलते-फूलते लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति शुतुरमुर्ग का रुख अपनाते हैं। ऐसे लोगों को सहन करना वाकई दर्दनाक होता है। उन्होंने कहा, देश के अंदर और बाहर वे हमारे लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थानों को नीचा दिखाने, निंदा करने, कलंकित करने के दुस्साहस में संलग्न हैं। यह चौंकाने वाला है कि जब आर्थिक विकास, नीति-निर्माण और कार्यान्वयन की बात आती है तो हममें से कुछ क्यों आनंदपूर्वक अपन लक्ष्यों का सहारा लेते हैं। इस अस्वास्थ्यकर रुख को समाप्त करने की जरूरत है।

NAGALAND STATE LOTTERIES
Draw Time: 01:00 PM
DEAR MAHANADI THURSDAY WEEKLY LOTTERY
Draw No:3 DrawDate on:20/04/23
1st Prize ₹1 Crore/- 72E 61245
Cons. Prize ₹1000/- 61245 (Remaining All Serial & Series)
2nd Prize ₹9000/-
04757 19785 30548 37159 40781 42711 50836 79146 82479 91240
3rd Prize ₹450/-
0408 2877 3217 4350 4833 6742 7594 8101 8132 9592
4th Prize ₹250/-
0741 1023 3086 5211 5476 6551 7846 9093 9123 9800
5th Prize ₹120/-
0000 0148 0272 0312 0351 0385 0406 0433 0597 0637
0714 0766 0799 1004 1127 1145 1276 1305 1776 1937
2006 2013 2238 2308 2557 2609 2656 2715 2800 2936
3274 3512 3667 3702 3764 3856 4169 4231 4233 4289
4333 4370 4378 4707 4785 4807 4948 5055 5144 5168
5192 5293 5554 5638 5704 5768 5821 5906 5976 5987
6020 6029 6164 6165 6307 6482 6510 6720 6954 6985
7124 7133 7200 7206 7217 7279 7323 7356 7396 7487
7730 8006 8195 8238 8248 8350 8610 8611 8794 8847
8849 9118 9131 9184 9307 9322 9497 9660 9698 9825
ISSUED BY : THE DIRECTOR
NAGALAND STATE LOTTERIES, KOHIMA, NAGALAND
For Results, Please Visit : Www.Nagalandlotteries.Com
KINDLY CHECK THE RESULT WITH THE OFFICIAL GAZETTE

NAGALAND STATE LOTTERIES
Draw Time: 06:00 PM
DEAR LAKE THURSDAY WEEKLY LOTTERY
Draw No:3 DrawDate on:20/04/23
1st Prize ₹1 Crore/- 86B 75188
Cons. Prize ₹1000/- 75188 (Remaining All Serial & Series)
2nd Prize ₹9000/-
05364 22514 39684 53963 55632 61717 74011 79890 84222 95706
3rd Prize ₹450/-
0897 1553 1574 1616 2500 4615 7009 7182 7484 9514
4th Prize ₹250/-
0503 0690 1079 1195 4742 6644 7724 8229 8389 8528
5th Prize ₹120/-
0031 0146 0591 0744 0908 0913 1066 1082 1229 1368
1395 1436 1619 1638 1742 1759 1770 1811 1898 1923
1953 1990 2012 2143 2316 2473 2487 2610 2646 2783
2947 2951 2954 2957 3109 3147 3193 3353 3744 3892
4099 4135 4155 4201 4319 4322 4344 4617 4648 4798
4819 4964 4977 5026 5132 5322 5380 5397 5623 5633
5703 5722 5912 5941 5957 5974 5987 6016 6099 6108
6162 6245 6720 6771 6845 6846 7088 7093 7239 7273
7521 7633 7757 8018 8123 8502 8503 8856 8906 9172
9224 9235 9244 9260 9420 9701 9855 9857 9865 9936
ISSUED BY : THE DIRECTOR
NAGALAND STATE LOTTERIES, KOHIMA, NAGALAND
For Results, Please Visit : Www.Nagalandlotteries.Com
KINDLY CHECK THE RESULT WITH THE OFFICIAL GAZETTE

NAGALAND STATE LOTTERIES
Draw Time: 08:00 PM
DEAR SANDPIPER THURSDAY WEEKLY LOTTERY
Draw No:3 DrawDate on:20/04/23
1st Prize ₹1 Crore/- 93J 07886
Cons. Prize ₹1000/- 07886 (Remaining All Serial & Series)
2nd Prize ₹9000/-
04135 08865 19984 32428 57363 72548 85159 88620 91723 92628
3rd Prize ₹450/-
2991 3217 3876 4224 4746 5345 6153 7202 8211 9247
4th Prize ₹250/-
0376 0622 2480 4905 5624 5727 6078 6803 8117 8475
5th Prize ₹120/-
0012 0091 0113 0170 0312 0488 0511 0691 0717 0979
1190 1275 1335 1385 1496 1534 1575 1605 1632 1891
1919 1926 2029 2136 2438 2506 2546 2666 2741 3281
3330 3362 3679 3732 3816 3920 3959 4043 4137 4155
4223 4501 4517 4570 4584 4640 4860 5032 5141 5144
5367 5626 5778 5887 5895 5899 5951 6114 6160 6212
6390 6563 6937 7038 7142 7179 7225 7311 7314 7399
7428 7474 7598 7665 7689 7991 7993 8036 8038 8069
8127 8133 8328 8474 8561 8591 8655 8877 9069 9100
9136 9209 9329 9412 9495 9565 9647 9679 9923 9952
ISSUED BY : THE DIRECTOR
NAGALAND STATE LOTTERIES, KOHIMA, NAGALAND
For Results, Please Visit : Www.Nagalandlotteries.Com
KINDLY CHECK THE RESULT WITH THE OFFICIAL GAZETTE

बात आगे बढ़े

आखिरकार समलैंगिक शादी से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार से सुनवाई शुरू कर दी। याचिकाकर्ताओं की सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है कि चूंकि अब देश में दो वयस्क लोगों का स्वेच्छा से आपस में समलैंगिक संबंध बनाना और एक साथ रहना अपराध नहीं है, इसलिए वे एक कपल के रूप में रह तो सकते हैं, लेकिन चाहकर भी अपने रिश्ते को शादी का नाम नहीं दे सकते क्योंकि शादी से जुड़े मौजूदा कानून जेंडर न्यूट्रल नहीं हैं। इनके मुताबिक शादी पुरुष और महिला के बीच ही हो सकती है। साफ है कि न केवल एलजीबीटीक्यू समुदायों से जुड़े लोग बल्कि कई मानवाधिकार कार्यकर्ता भी इसे समानता के अधिकार से जुड़े मसले के रूप में देख और समझ रहे हैं।

उनके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में दायर ये याचिकाएं कानून में निहित असमानता को दूर करने की एक कोशिश है, जिसे पॉजिटिव रूप में लेना चाहिए। मामला थोड़ा जटिल तब हो गया जब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करते हुए कहा कि शादियों से जुड़े इस मसले पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है। इसलिए कोर्ट को इस मामले की सुनवाई ही नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। केंद्र की दलील थी कि शादियों का यह विषय समवर्ती सूची में आता है। इसके अलावा विभिन्न धर्मों के पर्सनल लॉ भी इससे जुड़े हैं। जाहिर है, इसमें स्टेकहोल्डर्स का दायरा काफी व्यापक है। इसलिए कोर्ट को इसमें नहीं पड़ना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने पूरी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता का परिचय देते हुए केंद्र की इस दलील को आंशिक रूप से स्वीकार किया कि इसका दायरा काफी बड़ा है। उसने यह भी साफ कर दिया कि उसे अपनी सीमाओं का पूरा अहसास है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने पर्सनल लॉ से जुड़े पहलुओं को इस सुनवाई से अलग कर दिया। जाहिर है, अब मामला स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रावधानों को जेंडर न्यूट्रल करने की बहस तक सीमित हो गया है।

हालांकि इसके बाद केंद्र सरकार ने बुधवार को कोर्ट में एक और आवेदन दाखिल कर कहा कि उसने समलैंगिक शादी के मुद्दे पर तमाम राज्यों और केंद्र शासित इकाइयों से बातचीत और विचार-विमर्श की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

इसलिए इस केस में राज्यों को भी पार्टी बनाया जाए और केंद्र को यह मौका दिया जाए कि वह विचार-विमर्श की इस प्रक्रिया को पूरा कर सके। देखना होगा कि यह केस आगे क्या रूप लेता है और सुप्रीम कोर्ट समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता दिलाने की ओर बढ़ता है या नहीं। लेकिन आधुनिक मूल्यों वाले एक खुले समाज के रूप में यह हमारी जरूरत है कि समाज के सभी वर्गों को समानता और गरिमा से युक्त जीवन सुनिश्चित करने का संकल्प कमजोर न होने दिया जाए।

दलबदलुओं के लिए विचारधारा नहीं 'राजनैतिक कैरियर' महत्वपूर्ण

तनवीर जाफरी

कर्नाटक में राज्य विधानसभा हेतु 10 मई को चुनाव होने निर्धारित हैं। पूरे राज्य में एक ही चरण में होने वाले चुनाव की मतगणना 13 मई को होनी तय है। चुनाव पूर्व सर्वेक्षण से फिलहाल यही पता चल रहा है कि राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा को सत्ता में वापसी के लिये कड़ी मशक़्क़त करनी पड़ रही है। दूसरी तरफ़ कांग्रेस के पक्ष में भी सकारात्मक माहौल बनता दिखाई दे रहा है। भाजपा के विरुद्ध जहाँ सत्ता विरोधी रुझान है वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का कर्नाटक के बड़े क्षेत्र से होकर गुज़रना,तथा राहुल गांधी की संसद से बर्ख़ास्तगी के बाद राज्य में उनके प्रति पैदा हुई सहानुभूति कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने में कारगर साबित हो रही है। राज्य में होने वाले इस संभावित सत्ता परिवर्तन को राज्य के कई 'मंझे' हुये नेता भी बख़ूबी समझ रहे हैं। और उनकी यही 'दूरदर्शिता' उन्हें किसी न किसी परिस्थितिवश चुनाव पूर्व ही 'दल बदल ' करने के लिये 'मजबूर ' कर रही है। प्राप्त ख़बरों के अनुसार राज्य के आठ प्रमुख भाजपा नेताओं के अतिरिक्त तमाम 'छुटभैय्ये ' भाजपाई भी कांग्रेस पार्टी का दामन थाम चुके हैं। जबकि कुछ जे डी एस में भी शामिल हुये हैं। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व उप मुख्यमंत्री से लेकर कई विधायक और विधान परिषद सदस्य तक शामिल है। इसी सूची में सबसे महत्वपूर्ण नाम राज्य के पूर्व मुख्य मंत्री भाजपा एवं लिंगायत समुदाय के प्रभावशाली नेता जगदीश शेट्टार और पूर्व उपमुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी का है। कर्नाटक की राजनीति में लिंगायत समुदाय सत्ता का खेल बनाने बिगाड़ने में अत्यंत प्रभावी माना जाता है। बताया जा रहा है कि शेट्टार अपनी पारंपरिक सीट हुबली-धारवाड़ विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार के रूप में सातवीं बार चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन भाजपा ने उन्हें टिकट देने से मना कर दिया था। प्राप्त ख़बरों के अनुसार शेट्टार को हुबली-धारवाड़ विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी न बनाने के बदले में उन्हें केंद्र सरकार में मंत्री और उनके परिवार के किसी अन्य सदस्य को विधानसभा चुनाव लड़ने की पेशकश पार्टी की ओर से की गयी थी जो उन्होंने स्वीकार नहीं किया। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने आनन फ़ानन में जगदीश शेट्टार को पार्टी में शामिल कर उन्हें हुबली-धारवाड़ विधानसभा सीट से पार्टी का प्रत्याशी भी घोषित कर दिया। लिंगायत समुदाय के कर्नाटक में 18 फ़ीसद मतदाता हैं और वो प्राय: भाजपा के समर्थक माने जाते रहे हैं।

भाजपा छोड़ने के बाद जगदीश शेट्टार अकेले 20 से लेकर 25 लिंगायत प्रभाव वाली सीटों पर भाजपा को नुक़्सान व कांग्रेस को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। इनके अतिरिक्त भाजपा छोड़ने वाले प्रमुख नेताओं में पूर्व विधायक डीपी नारीबोल, मंत्री एस अंगारा और बीएस येदियुरख़्पा के क़रीबी डॉक्टर विश्वनाथ के साथ वर्तमान विधायक एमपी कुमारस्वामी, विधायक रामप्पा लमानी, विधायक गुली हटी शेखर, तथा वर्तमान एमएलसी (विधान पार्षद) शंकर शामिल हैं। दल बदल करने वाले अधिकांश भाजपा नेताओं का एक ही दुखड़ा है कि पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी क्यों नहीं बनाया। टिकट न मिलने के कारण पार्टी छोड़ने वाला एक नाम वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और कर्नाटक विधानसभा के पूर्व स्पीकर कागोडु थिम्मख़्पा की बेटी डॉ. राजनंदिनी का भी है। गत दिनों यह कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरख़्पा और पार्टी के अन्य सदस्यों की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हो गयीं । बीजेपी में शामिल होने बाद डॉ. राजनंदिनी ने अपनी 'व्यथा' बयान करते हुये कहा भी कि - 'मुझे उम्मीद थी कि कांग्रेस) मुझे पहचानेगी और मुझे टिकट देगी , लेकिन मुझे मौक़ा नहीं मिला जबकि बीजेपी में गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया गया। मैं पार्टी के लिए काम करूंगी। मैं वर्कर हूं और कहीं भी काम कर सकती हूं'। पूरी संभावना है कि डॉ. राजनंदिनी थिम्मप्पा भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगी।

केवल कर्नाटक ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों के चुनाव में भी यहाँ तक कि लोकसभा चुनावों के समय भी अपना अपना 'राजनैतिक कैरियर' बचाने या बनाने के नाम पर दल बदल का खेल चलना एक आम बात बन चुकी है। यह दल बदल पार्टी के टिकट मिलने या न मिलने से शुरू होकर मंत्री यहाँ तक कि मुख्यमंत्री बनने बनाने तक जारी रहता है। मध्य प्रदेश की तरह कई राज्य इस बात के भी उदाहरण पेश कर चुके हैं कि किस तरह सत्ता के इसी घिनौने खेल में राज्य की जनता द्वारा दिये गये सत्ता विरोधी जनमत का इन्हीं अवसरवादी व अपने स्वार्थपूर्ण राजनैतिक कैरियर को राजनैतिक विचारधारा से भी ऊपर मानने वालों द्वारा मज़ाक़ उड़ाया गया। आज भले ही कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में बड़ी संख्या में भाजपाई नेताओं को पार्टी में शामिल कराकर आगामी चुनाव में अपनी बढ़त की संभावनाओं का एहसास कर रही हो परन्तु जो नेता केवल भाजपा का टिकट न मिलने के कारण कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं वह कांग्रेस की विचारधारा के वाहक आख़िर कैसे हो सकते हैं ? अभी पिछले दिनों हिजाब के विरोध से लेकर और भी कई तरह के साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण के प्रयास भाजपा द्वारा कर्नाटक में इन्हीं वर्तमान विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र किये गये थे। उस समय तो यही भाजपा छोड़ने वाले लोग भाजपा की नीतियों का समर्थन कर रहे थे ?

कांग्रेस हो या भाजपा या अन्य परस्पर धुर विरोधी वैचारिक पार्टियां, इनके द्वारा अवसरवादिता के कारण ख़ास कर अपने राजनैतिक कैरियर को 'संवारने ' की ग़रज़ से दल बदल करने वाले लोगों को अपने अपने दलों में शामिल कराने का साफ़ अर्थ है कि पार्टियां स्वयं भी मात्र सत्ता प्राप्त करने के लिये ऐसे 'थाली के बैंगनों ' का सहारा लेना पसंद करती हैं जिनके लिये विचारधारा नहीं बल्कि उनका 'राजनैतिक कैरियर अधिक महत्वपूर्ण' है। और जिनकी कोई राजनैतिक विचारधारा ही न हो केवल उनका 'राजनैतिक कैरियर' ही उनके लिये सबसे महत्वपूर्ण हो वे वैचारिक रूप से किसी भी पार्टी के वफ़ादार तो हरगिज़ नहीं हो सकते।

राजनैतिक दल जो कि दरअसल प्राय: अवसरवादियों का ही एक समूह कहा जा सकता है यह भले ही अपना लाभ देखकर दलबदलुओं को टिकट,मंत्री पद यहां तक कि मुख्यमंत्री पद देकर अपने को मज़बूत और अपने विरोधी दलों को कमज़ोर करने का अस्थायी खेल खेलते रहते हों परन्तु जनता को ऐसे दलबदलुओं को तो ज़रूर सबक़ सिखान चहिये जिनके लिये विचारधारा नहीं बल्कि उनका स्वार्थपूर्ण राजनैतिक कैरियर ही सबसे महत्वपूर्ण है।

एक 'राष्ट्रीय' सिविल सेवा की ओर- 'भावना वृक्ष'

श्रीनिवास कटिकिथला
निदेशक
एलबीएसएनएए

सिविल सेवा दिवस, जो प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को मनाया जाता है, राष्ट्रीय सिविल सेवा के विचार का एक उत्सव है। मणिबेन पटेल ने अपनी डायरी में लिखा, 'बापू ने दिल्ली में नये सेवा भर्ती स्कूल का उद्घाटन किया। यह एक मर्मस्पर्शी क्षण था। सरदार पटेल ने 1947 में नव गठित भारतीय प्रशासनिक सेवा की शुरुआत की, 'पूरी तरह से भारतीय अधिकारी के साथ और पूरी तरह से भारतीय नियंत्रण के अधीन ... अतीत की परंपराओं और कुप्रभावों के बिना, राष्ट्रीय सेवा की अपनी वास्तविक भूमिका को अपनाने के लिए स्वतंत्र। उन्होंने एक मूलमंत्र दिया, जो प्रत्येक सिविल सेवा अधिकारी को प्रेरित कर सकता है: हमें भारत में प्रत्येक सिविल सेवा अधिकारी से सर्वश्रेष्ठ की अपेक्षा करने का अधिकार है, चाहे वह किसी भी जिम्मेदारी के पद पर क्यों न हो। यह आपके लिए नहीं है कि आप अपने कार्य को विशुद्ध रूप से किसी अन्य दृष्टिकोण से या पूरी तरह से स्वार्थ से वशीभूत होकर करें, चाहे वह अधिकारी कितना भी प्रबुद्ध क्यों न हो। आपका सर्वप्रथम विचार यह होना चाहिए कि समग्र रूप से भारत के कल्याण में कैसे योगदान दिया जाए। इसलिए, सरदार पटेल के वाक्यांश 'स्टील फ्रेम' को एक कठोर, प्रतिबंधात्मक और नियम-बद्ध औपनिवेशिक नौकरशाही के नकारात्मक अर्थ से जोड़ना हास्यास्पद है।

1921 के कॉमन्स डिबेट में ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड लॉयड जॉर्ज द्वारा इंपीरियल सिविल सर्विस (आईसीएस) के वर्णन के दौरान 'स्टील फ्रेम' को सिविल सेवा की लोकप्रिय संस्कृति और स्व-परिकल्पना दोनों को परिभाषित करने के लिए प्रयुक्त किया गया था। इसलिए, राष्ट्रीय लोकाचार में निहित एक सिविल सेवा को तैयार करने की शुरूआती सरकारों की चिंताएं, ध्यान-केंद्र से विचलित हो गयीं, क्योंकि वह देश-विभाजन का अशांत दौर था। यह काम अधूरा रह गया।

सिविल सेवा के लिए एक भारतीय लोकाचार को परिभाषित करने का कार्य भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संबोधन के साथ शुरू हुआ, जहां उन्होंने भारत को 'अमृत महोत्सव' से 'अमृत काल' की ओर ले जाने के लिए, देश की दृष्टि और 'पंच प्रण'- पांच संकल्प - की व्याख्या की।

दूसरा संकल्प अर्थात औपनिवेशिक मानसिकता को समाप्त करने के लिए स्व-परिकल्पना के पुनरीक्षण और सिविल सेवाओं से जुड़ी औपनिवेशिक कार्य-संस्कृति को हटाने की जरूरत है। एक प्रतिबिम्ब की शक्ति और सकारात्मक दृष्टि, दोनों मुक्तिदायक हैं और सुधार करने में सक्षम हैं। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए) ने सिविल सेवा को एक जीवित इकाई पीपल वृक्ष - जिसने प्राचीन काल से हमारी सभ्यतागत दृष्टि को अनुप्राणित किया है, के रूप प्रस्तुत किया। सिविल सेवा, 'भावना वृक्ष' के रूप में, 'सेवा और सहानुभूति' का एक वृक्ष है। इस प्रकार, यह आत्म-आश्वासन और उपनिवेशवाद की भावना से मुक्ति की सकारात्मक पुनर्पुष्टि है।

नागरिकों के कल्याण में स्वर्ग-तुल्य आराम की तलाश के लिए प्रेरक कुलदेवता, शक्तिशाली स्वर्गारोहिणी की अग्रभूमि में स्थापित अकादमी, भावना वृक्ष की एक प्रतीक के रूप में परिकल्पना करती है, जो निस्वार्थ सेवा और कर्तव्य के प्रति समर्पण के कालातीत गुणों का प्रतिनिधित्व करता है। अमृत काल के लिए एक आदर्श सिविल सेवा अधिकारी की विशेषताओं और अवधारणा को पहली बार 31 अक्टूबर 2019 को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में प्रधानमंत्री द्वारा प्रतिपादित किया गया था।

ये हैं - (1) सक्रिय और विनम्र (2) पेशेवर और प्रगतिशील (3) ऊर्जावान और सक्षम (4) पारदर्शी और तकनीक-सक्षम (5) रचनात्मक और सकारात्मक (6) कल्पनाशील और अभिनव। भविष्य के लिए तैयार सिविल सेवा के विचार में समग्रता है। एक पूरी सरकार और मिलकर काम करने का दृष्टिकोण, भविष्य का अंदाज लगाना, कार्य-प्रणाली में सहयोगी, संवाद व कार्यों के प्रति भागीदारी की भावना तथा स्वभाव से अभिनव। दूर-दराज के क्षेत्रों में लोगों की सेवा करने वाले 'भावना वृक्ष' की यही प्रकृति है।

पूर्व औपनिवेशिक मानसिकता को समाप्त करना, भारतीय मूल्यों के प्रति गर्व की भावना को साझा करना और राष्ट्र-प्रथम दृष्टिकोण के साथ कर्तव्य-बद्ध सिविल अधिकारियों का समूह, सिविल अधिकारियों की नई नैतिकता है, जो इसके पवित्र दरवाजे से, 'मसूरी वाला कर्मयोगी के रूप में बाहर निकलते हैं। अकादमी गीत के रिंगिंग नोट्स, हाओ धर्मेते धीर, हाओ करोमेते बीर, हाओ उन्नतो शिर-नहीं भाय, कार्य करने के लिए उनका आध्यात्मिक आह्वान है।

'भावना वृक्ष' के लोकाचार की याद में 'सेवा का मार्ग' है, जिसे अकादमी के प्रतिष्ठित डायरेक्टर्स स्क्वायर के चारों ओर बनाया गया है। मार्ग कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित, भली-भांति बंद समय कैप्सूल की एक श्रृंखला है, जिनमें 2021 में शुरू होने और 2047 में समाप्त होने वाले सिविल सेवा प्रशिक्षुओं के क्रमिक बैचों के उद्देश्य के बयानों को समाहित किया जा रहा है। इन प्रतिबद्धता बयानों को विकसित भारत के तहत 15 अगस्त, 2047 को, भारतीय सदी की सुबह में अनावरण के लिए संरक्षित किया जा रहा है। 'भावना वृक्ष' के लिए - अपने स्वामी, अर्थात भारत के लोगों के एक सक्षम सेवक के रूप में खुद को मुक्त करने का दिन।

इस प्रकार, पूर्ववर्ती औपनिवेशिक 'स्टील फ्रेम' प्रतिमान को दरकिनार करते हुए और सरदार के आह्वान को साकार करते हुए, '...अब, आप अपने ही लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो अब, आप अपने दिल, दिमाग और आत्मा के साथ सेवा कर सकते हैं... आप अपने लोगों की सेवा करके वास्तव में भारतीय होंगे।

सरकार पान मसाला एवं तंबाकू के गुटखों पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगा पा रही

डॉ. सुरजीत सिंह गांधी

हाल में सर्वोच्च अदालत की इस तल्ख टिप्पणी ने सबका ध्यान खींचा है कि सरकार पान मसाला एवं तंबाकू के गुटखों पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगा पा रही।

समाज को भी उन प्रश्नों पर विचार करना होगा कि वास्तव में सरकार इसे नियंत्रित क्यों नहीं कर पा रही: क्या हमारे कानून अपर्याप्त हैं? क्या कानूनों में अस्पष्टता है? गुटखा कंपनियों का व्यवहार निरंकुश क्यों है? गुटखा कंपनियों का विज्ञापन करने वाले रोल मॉडल का क्या कोई सामाजिक दायित्व नहीं है? क्या निरक्षरता इसका प्रमुख कारण है? गुटखे की पीक से लाल दीवारों से क्या हम स्वच्छ भारत की दिशा में बढ़ सकेंगे?

भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा तंबाकू उपभोक्ता देश है। ग्लोबल यूथ टोबाको सर्वे, 2019 के अनुसार भारत में 15 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 26.7 करोड़ लोग तंबाकू का सेवन करते हैं यानी हर 5वां भारतीय तंबाकू का सेवन कर रहा है। भारत में तंबाकू एवं पान मसाला गुटखा का बाजार 40 हजार करोड़ रुपये से अधिक का है। ऐसे में गुटखा निर्माता कंपनियां बाजार पर पकड़ बनाए रखने के लिए सारे तरीके इस्तेमाल करती हैं। भारत में तंबाकू लॉबी इतनी मजबूत है कि राजनीतिक दलों पर उनका बहुत गहरा प्रभाव है। तंबाकू की खपत के खिलाफ कोई भी कार्रवाई राजनीतिक मुद्दा बन जाएगी और उन लोगों की लोकप्रियता को प्रभावित करेगी जिन्होंने प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। गुटखा निर्माता इस बात को भी अच्छी प्रकार से जानते हैं कि सरकार गुटखा कभी बंद नहीं करवा सकती।

यदि सरकार गुटखा पर प्रतिबंध लगाना भी चाहे तो नशा करने की आदत पर प्रतिबंध कैसे लगाएगी? यदि गुटखे पर प्रतिबंध लगा भी दिया जाता है तो इसकी कालाबाजारी बढ़ जाती है जिससे गुटखा निर्माता कंपनियों के लाभ कम होने की बजाय और अधिक बढ़ जाते हैं। इसका प्रमुख कारण है कि भारत की 25 प्रतिशत निरक्षर और 40 प्रतिशत केवल साक्षर जनता को गुटखा निर्माता कंपनियों ने आकषर्क विज्ञापनों द्वारा मनोवैज्ञानिक रूप से गुलाम बना रखा है। आज के युवाओं में उद्देश्यहीनता के कारण इन विज्ञापनों में दिखाई जाने वाली टैगलाइन जैसे: कुछ कर ऐसा दुनिया बनना चाहे तेरे जैसा से बहुत प्रभावित होते हैं। गुटखा एवं तंबाकू को खाकर उन्हें लगता है कि वे भी वही सब कुछ कर सकते हैं, जो उनका हीरो करता है। विज्ञापनों के मनोविज्ञान का लाभ लेकर गुटखा निर्माता कंपनियां बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगवाती हैं कि न चाहकर भी लोगों का पान मसाला गुटखा पर ध्यान निरंतर बना रहे।

दोस्तों के साथ शौकिया या फिर बड़ों की देखा देखी नये-नये युवाओं को गुटखा खाने की इतनी लत लग जाती है कि वे पान मसाला के एडिक्ट हो जाते हैं। यद्यपि पान मसाला, गुटखा, जर्दा, खैनी आदि बनाने वाली कंपनियां दावा करती हैं कि वे प्रसंस्कृत तंबाकू बेचती हैं। इसमें रसायनों के साथ इलायची, लौंग और केसर, फ्लेवर जैसी सामग्री मिलाकर तंबाकू को स्वादिष्ट बनाया गया है। यह गुटखा हर साइज और हर कीमत में आसानी से उपलब्ध है।

तंबाकू के बढ़ते सेवन को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा निरंतर प्रतिबंध लगाए जाते रहे हैं। 2003 में सीओटीपीए एक्ट के कारण गुटखा के विज्ञापन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। गुटखा निर्माता कंपनियों ने अधिनियम के छिद्रों का लाभ लेते हुए गुटखा के विज्ञापन को इलायची ब्रांड के नाम के साथ प्रोमोट करना शुरू कर दिया जबकि वे स्पष्ट रूप से पान मसाला और तंबाकू के गुटखे का ही प्रचार करती हैं। सभी कंपनियां अपने विज्ञापन का मनोवैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल कर गुटखा का उपयोग कम नहीं होने देतीं।

2011 में फेडरल फूड सेफ्टी एंड रेग्युलेशन एक्ट के अंतर्गत व्यवस्था की गई कि कोई कंपनी अपने उत्पादों में तंबाकू मिला कर बेचेगी तो उसे बैन कर दिया जाएगा। तंबाकू को बेचने पर प्रतिबंध न होने के कारण कंपनियों ने पान मसाला और तंबाकू के दो पाउच बनाने शुरू कर दिए। 2011 के अधिनियम में यह व्यवस्था भी की गई सरकार एक निश्चित समय के लिए इन उत्पादों पर बैन लगा सकती है। इस एक्ट के अंतर्गत मई, 2013 तक 24 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों में गुटखे पर रोक लगा दी गई थी। इसके बावजूद गुटखे की मांग बनी रही।

जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि लोग जानते हैं कि तंबाकू सेवन उनके स्वास्थ्य के लिए जहर है, इसके बावजूद वे अपनी मौत को खरीदने के लिए पैसे देते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार विश्व में प्रति वर्ष लगभग 80 लाख मौतें और भारत में 2.3 लाख मौतें तंबाकू सेवन के कारण होती हैं।

राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की वेबसाइट के अनुसार तंबाकू के सेवन के कारण भारत में प्रति दिन 3500 लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है। देश में होने वाले कैंसर में से 70 प्रतिशत से अधिक मामले मुंह के कैंसर के होते हैं, जिसका प्रमुख कारण पान मसाला और तंबाकू ही है। एक शोध के अनुसार तंबाकू चबाना तंबाकू खाने का सबसे खराब तरीका है, और मानव शरीर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है।

आम तौर पर गुटखा खाने वाला औसतन 3 से 4 गुटखा प्रति दिन खा लेता है। यदि इसे वर्ष के आधार पर जोड़ा जाए तो साल में एक व्यक्ति औसतन 6000 से 6500 रुपये का गुटखा चबा जाता है। यदि इसे कुल तंबाकू खाने वालों की संख्या के आधार पर निकाला जाए तो रकम लाखों करोड़ों में है जबकि सरकार को मिलने वाला राजस्व स्वास्थ्य पर किए व्यय की तुलना में बहुत कम होता है। 2020 में सरकार को तंबाकू से 1234 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ था जबकि सरकार ने तंबाकू से होने वाली बीमारियों पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से 1,77,000 करोड़ व्यय किए थे। यदि सरकार इसे रोकने में स्वयं को असमर्थ महसूस करे तो उसे इस पर से प्रतिबंध हटाने के साथ एक निश्चित नियमावली के साथ बेचने की छूट देनी चाहिए क्योंकि तंबाकू पर लगने वाले प्रतिबंधों के कारण लोग अन्य अधिक शक्तिशाली दवाओं की ओर मुड़ सकते हैं।

सरकार को इस पर भारी कर आरोपित करना चाहिए। करों से होने वाली आय से तंबाकू के दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक करे। गुटखा जैसी दिखने वाली वस्तुओं के विज्ञापनों एवं इसको प्रोत्साहित करने वाले सभी प्रकार के विज्ञापनों पर रोक लगनी चाहिए।

बॉडी नहीं बनाती ओमेगा-3, शाकाहारी लोगों के लिए बहुत जरूरी हैं ये बीज

ओमेगा 3 एक जरूरी फैटी एसिड है, जिसे शरीर नहीं बना पाता है। इसलिए इसकी कमी का खतरा काफी ज्यादा होता है। जिससे बचने के लिए इन फूड्स का सेवन करना चाहिए।

शरीर को कई तरह के फैट की जरूरत होती है ताकि शरीर का काम सही चलता रहे। मगर ओमेगा-3 फैटी एसिड को बॉडी खुद नहीं बना पाती है और उसे फूड्स पर निर्भर रहना पड़ता है। वरना शरीर में इसकी भारी कमी हो सकती है।

सेल्स के फंक्शन के लिए यह न्यूट्रिएंट बहुत जरूरी होता है। शरीर में ओमेगा-3 की कमी से कई सारी दिक्कतें होने लगती हैं। जिनके बारे में न्यूट्रिशनिस्ट किरण कुकरेजा ने जानकारी दी है। एक्सपर्ट ने इसे पाने के लिए कुछ फूड्स खाने की सलाह भी दी है।

ओमेगा-3 की कमी से झेलनी होगी ये दिक्कतें

ड्राई स्किन, हेयर और आई

हेल्दी स्किन और हेयर के लिए ओमेगा-3 फैटी एसिड बहुत जरूरी है। वहीं, आंखों की नमी और रेटिना में इसका हाई कंसंट्रेशन होता है। इसलिए इसकी डेफिशिएंसी त्वचा, बाल और आंखों में रूखापन कर सकती है।

नाखून हो जाएंगे कमजोर

नाखूनों की सेल्स को जोड़े रखने के लिए भी यह फैट जरूरी होता है। इसके कम होने पर सेल्स मेंब्रेन ढीले और कमजोर होने लगते हैं। जिससे नाखून कमजोर और नाजुक हो जाते हैं।

बीमारियों का घर बनेगा दिल

ओमेगा-3 फैटी एसिड की कमी से दिल बीमारियों का घर बन सकता है। क्योंकि, यह कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। जो कि नसों को सिकोड़ने और डैमेज करके दिल की बीमारियों का प्रमुख कारण बनती हैं।

शाकाहारी लोगों के लिए ओमेगा-3 फूड

शाकाहारी लोग इसे पाने के लिए अलसी के बीज, चिया सीड्स और अखरोट का सेवन कर सकते हैं। इनमें इसका प्रकार अल्फा लिनोलेनिक एसिड (एएलए) प्रचुर मात्रा में होता है। साथ में फोर्टिफाइड दूध, योगर्ट आदि का सेवन भी कर सकते हैं।

ओमेगा-3 के नॉन वेजिटेरियन फूड

मछलियों में ओमेगा-3 फैट काफी होता है। इसके लिए सैल्मन, मैक्रेल, टूना, सार्डिन आदि फैटी फिश का सेवन कर सकते हैं।

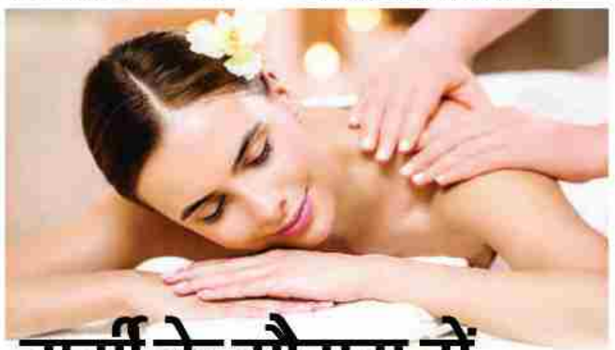

गर्मी के मौसम में मसाज के फायदे

गर्मियों का मौसम आ चुका है। इस मौसम में बाहर निकलने पर बढ़ती धूप और गर्म हवा आपको परेशान कर देती है। इसके अलावा रोज की भागदौड़ भरी दिनचर्या लोगों को थका देती है। इसके बाद शरीर पर थकान हावी हो जाती है। इसके बाद कुछ भी करने का मन नहीं करता है। यदि आपको इस मौसम में तरोताजा रहना है तो मसाज एक अच्छा उपाय हो सकता है। मसाज लेने के बाद आप एक बार फिर से तन और मन से ताजगी महसूस करने लगते हैं।

मसाज के फायदे

- मसाज से मांसपेशियो की सिकुड़ने और फैलने की क्षमता में बढोत्तरी होती है। इसके अलावा मेटाबॉलिजम का कार्य सही से होने लगता है।
- मसाज से ब्लड सर्कुलेशन सुचारु रूप से काम करता है।
- मसाज करने से नींद अच्छी आती है। जिसके चलते आंखों की रोशनी बढ़ती है। और स्किन चमकदार बन जाती है।
- मसाज करने के दौरान लंबी-लंबी सांसें लेने से शरीर के अंदर मौजूद कई विकार बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद शरीर में स्फूर्ति आ जाती है।
- मसाज रोज करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है।
- मसाज से रंग में निखार आता है और स्किन चमकदार बन जाती है।
- मसाज से मस्तिष्क में तरावट एवं मानसिक शक्ति का अनुभव होता है।
- मसाज के बाद स्किन के छिद्रों में तेल भरे रहने से जीवाणुओं शरीर के अंदर जाने का खतरा नहीं रहता है।

इनकी भी होती है मसाज

- माथे की मसाज
- गालों की मालिश
- ठुडडी की मसाज
- गर्दन की मसाज

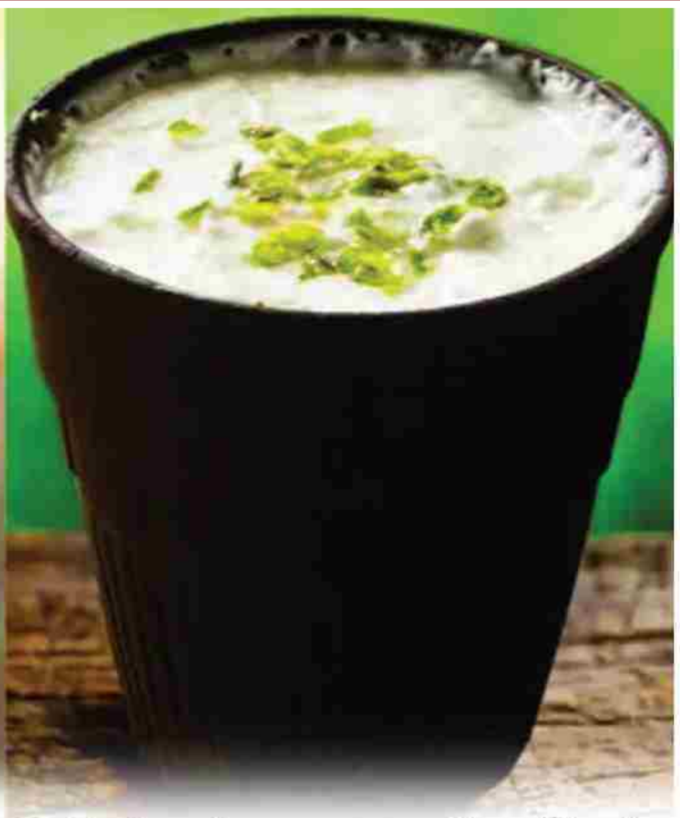

गर्मियों में खाएं ये चीजें चिलचिलाती गर्मी में भी शरीर रहेगा ठंडा

गर्मियों में तेज धूप, पसीना, गर्म हवाओं की वजह से शरीर में पानी की कमी यानी शरीर में डिहाइड्रेशन पैदा कर सकती है। इस मौसम में शरीर से सारे इलेक्ट्रोलाइट्स निकलने का खतरा होता है।

भारत में गर्मियों का मौसम जारी है और कई जगहों पर पारा 40 डिग्री को भी पार कर गया है। गर्मी की वजह से घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। भाषण गर्मी में पंखा और कूलर भी साथ नहीं दे रहे हैं। अगले कुछ हफ्तों में गर्मी का सितम और बढ़ेगा और ऐसा वक्त आ जाएगा जब एसी भी काम नहीं करेगी। जाहिर है गर्मी का शरीर पर सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है।

गर्मियों में तेज धूप, पसीना, गर्म हवाओं की वजह से शरीर में पानी की कमी यानी शरीर में डिहाइड्रेशन पैदा कर सकती है। इस मौसम में शरीर से सारे इलेक्ट्रोलाइट्स निकलने का खतरा होता है। लंबे समय तक डिहाइड्रेशन की वजह से चक्कर आना, सिरदर्द, ऊर्जा की कमी, भ्रम और यहां तक कि बेहोशी जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। डाइट एक्सप्रेशन की फाउंडर और न्यूट्रिशनिस्ट पारुल के अनुसार, गर्मियों में डिहाइड्रेशन से बचने के लिए सिर्फ पानी काफी नहीं है। आपके खाने में कार्ब्स, विटामिन और मिनरल वाली चीजें भी उतनी ही जरूरी हैं। कुछ चीजें हैं जिनका गर्मियों में सेवन करने से शरीर को ठंडा रखा जा सकता है और किसी भी तरह की समस्या से बचा जा सकता है।

केला और अवोकेडो

इन दोनों फलों में कार्ब्स की मात्रा अधिक होती है। इसके अलावा यह फाइबर के अच्छे स्रोत हैं। यह दोनों इलेक्ट्रोलाइट का लेवल बनाए रखते हैं। इन दोनों का शरीर पर ठंडा प्रभाव पड़ता है।

लौकी परिवार की सब्जियां

गर्मियों के दिनों शरीर को ठंडा रखने के लिए आपको लौकी परिवार की सब्जियां जैसे लौकी, कद्दू, करेला, तुरई आदि का खूब सेवन करना चाहिए। इनमें पानी की मात्रा होने के साथ सभी जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं।

साब्जा सीडस

इन छोटे-छोटे बीजों में फाइबर और प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। इसके अलावा यह ओमेगा-3 फैटी एसिड, पोटैशियम, विटामिन सी आदि का भी भंडार है। यह तत्व गर्मी को कम करते हैं और पेट को ठंडा रखते हैं।

खट्टे फल

जूस वाले खट्टे फल जैसे संतरे, नींबू, कीनू और मौसंबी आदि में जरूरी पोषक तव जैसे विटामिन ए, बी और सी पाया जाता है। यह शरीर में इलेक्ट्रोलाइट का लेवल बनाए रखते हैं।

दही

घर की बनी दही पोषक तत्वों का खजाना है और यह पेट के लिए एक नैचुरल प्रोबायोटिक है, जो शरीर को ठंडा रख सकती है। आप खाने में दही या इसका रायता बनाकर इस्तेमाल करें।

खून की नसों में चिपके जिद्दी कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकाल देंगे गर्मियों के ये 5 फल

आजकल सिर्फ व्यस्क ही नहीं बल्कि युवाओं को भी इसका सामना करना पड़ रहा है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि खराब खानपान और सुस्त जीवनशैली इसका सबसे बड़ा कारण हैं। कुछ खाद्य पदार्थ खून की नसों में जमा खराब कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने का काम करते हैं। इनमें गर्मियों में मिलने वाले कुछ फल भी शामिल हैं।

कोलेस्ट्रॉल बढ़ना आजकल की एक गंभीर और आम समस्या बन गई है। आजकल सिर्फ व्यस्क ही नहीं बल्कि युवाओं को भी इसका सामना करना पड़ रहा है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि खराब खानपान और सुस्त जीवनशैली इसका सबसे बड़ा कारण हैं। यह कोई आम समस्या नहीं है और इससे दिल से जुड़े रोगों, स्ट्रोक यानी दिमाग का दौरा और हार्ट अटैक जैसी गंभीर और जानलेवा बीमारियों का खतरा है। कोलेस्ट्रॉल शरीर की हर कोशिका में पाया जाता है। यह शरीर के लिए जरूरी भी है लेकिन वो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है। अच्छा कोलेस्ट्रॉल खाद्य पदार्थों का पाचन, हार्मोन का उत्पादन और अन्य कई काम करता है। यह सभी कचरे और विषाक्त पदार्थों को वापस लीवर में पहुंचाता है। लेकिन एक खराब कोलेस्ट्रॉल भी है, जो धमनियों की दीवारों पर पट्टिका की एक परत बनाता है, जिससे रक्त का प्रवाह मुश्किल हो जाता है, जो आगे चलकर हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज और स्ट्रोक का कारण बन सकता है।

कुछ खाद्य पदार्थ खून की नसों में जमा खराब कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने का काम करते हैं। इनमें गर्मियों में मिलने वाले कुछ फल भी शामिल हैं। चूंकि गर्मियों का मौसम जारी है, तो ऐसे में आपको इन सस्ते फलों का खून सेवन करना चाहिए जिससे शरीर से यह गंदा पदार्थ बाहर निकल सके और आपका ब्लड सर्कुलेशन बेहतर बना रहे।

पपीता

फाइबर से भरपूर पपीता हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। यह खराब कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल करता है। फाइबर पाचन को बेहतर बनाने में सहायक है और यह आंतों की भी सफाई करता है।

अंगूर

एनसीबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, अंगूर फाइबर का एक बेहतर स्रोत है। इस तरह अंगूर का नियमित सेवन कोलेस्ट्रॉल लेवल को नैचुरली कम करने में मदद करता है। अंगूर वजन को नियंत्रित करने में भी मदद करता है, जिसे हृदय रोगों के पीछे एक और कारण बताया जाता है।

खट्टे फल

गर्मियों में सभी तरह के खट्टे फल खाना दिल से जुड़ी बीमारियों को दूर करने में फायदेमंद साबित हो सकते हैं। आप अपने खाने में नींबू और संतरे जैसे खट्टे फल शामिल कर सकते हैं क्योंकि यह विटामिन सी से भरे होते हैं, जो इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाते हैं।

सेब

सेब एक ऐसा फल है, जो सिर्फ कोलेस्ट्रॉल ही नहीं बल्कि शरीर में जमा अन्य गंदे पदार्थों को भी कम कर सकता है. सभी हृदय रोगियों को अपने खाने में सेब को शामिल करना चाहिए क्योंकि यह कोलेस्ट्रॉल लेवल को नैचुरली कम करने में मदद करता है। सेब में फाइबर पेक्टिन की मौजूदगी कोलेस्ट्रॉल लाल को कम करने में मदद करती है।

स्ट्रॉबेरी

एनसीबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए स्ट्रॉबेरी एक बेहतर फ्रूट है। यह एंटीऑक्सिडेंट का बेहतर स्रोत है, जो कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसके अलावा यह विटामिन का भंडार है और इसमें कैलोरी बहुत कम होती है।

स्वाद के साथ सेहत की खान है आम

स्वाद के साथ फायदों की खान है आम। जी हां, आम को फलों का राजा माना जाता है। गर्मियां तो बिना आम के सेवन अधूरी है। आप कोई भी फल खा लें लेकिन आम को अपनी फ्रूट बास्केट में शामिल करना न भूलें। स्वाद के साथ आम खाने के कई फायदे हैं।

कैंसर से बचाव

आम में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट कोलोन कैंसर, ल्यूकेमिया और प्रोस्टेट कैंसर से बचाव में फायदेमंद है। इसमें क्यूर्सेटिन, एस्ट्रागालिन और फिसेटिन जैसे ऐसे कई तत्व होते हैं जो कैंसर से बचाव करने में मददगार होते हैं।

कोलेस्ट्रॉल नियमित रखने में

आम में फाइबर और विटामिन सी खूब होता है। इससे बैड कोलेस्ट्रॉल संतुलन बनाने में मदद मिलती है।

पाचन क्रिया को ठीक रखने में

आम में ऐसे कई एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन को तोड़ने का काम करते हैं। इससे भोजन जल्दी पच जाता है। साथ ही इसमें उपस्थित साइट्रिक एसिड, टरटैरिक एसिड शरीर के भीतर क्षारीय तत्वों को संतुलित बनाए रखता है।

स्मरण शक्ति में मददगार

जिन लोगों को भूलने की बीमारी हो उन्हें आम का सेवन करना चाहिए। इसमें पाया जाने वाला ग्लूटामिन एसिड नामक एक तत्व स्मरण शक्ति को बढ़ाने में उत्प्रेरक की तरह काम करता है। साथ ही इससे रक्त कोशिकाएं भी सक्रिय होती हैं। इसीलिए गर्भवती महिलाओं को आम खाने की सलाह दी जाती है।

त्वचा के लिए है फायदेमंद

आम के गुदे का पैक लगाने या फिर उसे चेहरे पर मलने से चेहरे पर निखार आता है और विटामिन सी संक्रमण से भी बचाव करता है।

मोटापा कम करने में

मोटापा कम करने के लिए भी आम एक अच्छा उपाय है। आम की गुठली में मौजूद रेशे शरीर की अतिरिक्त चर्बी को कम करने में बहुत फायदेमंद होते हैं। आम खाने के बाद भूख कम लगती है, जिससे ओवर ईटिंग का खतरा कम हो जाता है।

रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में

आम खाने से शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता में भी इजाफा होता है।

बच्चों को सिखाएं हेल्दी फूड हैबिट

बच्चों के बड़े होने पर उन्हें पोषण देने के लिए जरूरी है कि बचपन से ही उन्हें अच्छा पोषण दिया जाए। लेकिन उसके लिए सही शुरुआत करें और स्वस्थ खाना सिखाएं। बच्चे इन स्वस्थ आदतों को खुद अनुभव करके और दूसरों को देखकर सीखते हैं।

बच्चों को अच्छी खाने की आदतें सिखाना शुरू करना कभी भी जल्दी नहीं होता है। इसके लिए आप नीचे दिए टिप्स भी अपना सकते हैं जिससे बच्चे सही समय पर स्वस्थ खाना सीखें जो उन्हें बड़े होने तक फायदा पहुंचाएगा।

सभी साथ बैठकर खाएं

एक परिवार के रूप में एक साथ खाना खानाज जरूरी है। बच्चों को सिखाएं कि सभी साथ बैठें। इससे बच्चों के सामने आप हर तरह की सब्जियां खाकर दिखाएंगे तो वो भी आपसे सीखेंगे। साथ ही उन्हें लोगों के सामने व्यवहार करना भी आएगा। इससे एक फायदा होगा कि बच्चा खाना खाते समय फोन या टीवी भी नहीं देखेगा।

बच्चों को चुनने दें

जरूरी नहीं जो हम खा रहे हों वो सभी चीजें बच्चे खाएं। बच्चों के लिए अलग से खाना न बनाएं लेकिन जो आप बना रहे हैं या बड़े खा रहे हैं वो सभी चीज बच्चों को जबरदस्ती न खिलाएं। बच्चों को खुद चुनने दें कि वो इन सबमें से क्या खाना चाहते हैं।

अपनी कोशिश जारी रखें

बच्चों को हेल्दी फूड हैबिट सिखाने में समय लग सकता है। ऐसे में अपनी कोशिश न छोड़ें। शुरुआत में बच्चे नखरे करेंगे लेकिन आपकी कोशिश जारी रही तो बच्चों की आदत भी बदलेगी। कभी-कभी बच्चों को यह चुनने दें कि खाने में क्या सब्जी बननी चाहिए। साथ ही उन्हें उसे बनाने में मदद के लिए कहें।

लालच देकर न खिलाएं

बच्चों को लालच देकर खाना खत्म करने को न कहें। बच्चों को डेजर्ट के लालच में खाना खाने को न कहें। कई माता-पिता इस बात पर जोर देते हैं कि अगर बच्चे पूरा खाना खाएंगे तो उन्हें मिठाई मिलेगी। ऐसा न करें। उन्हें भूख के अनुसार खाना सिखाएं।

भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर लगाया गंभीर आरोप

नई दिल्ली। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने प्रेस वार्ता कर कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा पावर डिस्कॉम को दी गई पावर सब्सिडी के सीएजी एंपैनलमेंट ऑडिटर्स से ऑडिट का दिल्ली सरकार का फैसला एक बहुत बड़ा छलावा है और दिल्ली की जनता और भाजपा इसे स्वीकार नहीं करेगी। सचदेवा ने कहा है कि गत 8 साल से अधिक अरविंद केजरीवाल सरकार पावर डिस्कॉमों को बिजली सब्सिडी बिना किसी ऑडिट मैकेनिज्म के देती रही है।

सचदेवा ने आगे कहा कि सच यह है कि पावर डिस्कॉम में दिल्ली सरकार एवं निजी कंपनियां बराबर की भागीदार हैं और पावर डिस्कॉम बोर्ड में आम आदमी पार्टी नेताओं की

नियुक्ति की पोल खुलने के बाद से यह सवाल उठता रहा है कि पावर डिस्कॉमों को दी गई सब्सिडी का एक हिस्सा क्या किसी ना किसी रूप में आम आदमी पार्टी को वापस मिलता है। सचदेवा ने कहा कि गत 6 साल से पावर डिस्कॉम के ऑडिट को लेकर दिल्ली सरकार का एक मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। जिस पर तारीख ही नहीं पड़ रही है। केजरीवाल सरकार ने आज तक उसमें तारीख लगवाने के लिए कोई कानूनी प्रयास नहीं किया। प्रेस वार्ता में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि बिजली एक्ट्स और ऑडिट कराने के लिए बिजली अधिनियम 2003 की धारा-108 लागू की जानी चाहिए थी, ताकि ऑडिट अनिवार्य हो जाए, लेकिन सरकार ने आज तक उस धारा को लागू नहीं किया। बिधूड़ी ने कहा कि अगर सीएजी ऑडिट होता, तो यह सच्चाई सामने आती कि बिजली चोरी रुकने से कंपनियों का कितना लाभ हुआ है और उसका लाभ जनता तक पहुंचना चाहिए था।

आईपीएल खेल रही दिल्ली केपिटल टीम का लाखों का क्रिकेट किट-बैट-ग्लोब्स-पैड चोरी

नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में भाग ले रही दिल्ली कैपिटल की टीम का लाखों का बैट, पैड, जूते, ग्लोब्स आदि चोरी हो गए हैं। दिल्ली टीम का अरुण जेटली स्टेडियम में कल गुरुवार को कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ मैच होना है।

बेंगलुरु से दिल्ली कैपिटल की टीम आईजीआई एयरपोर्ट पर पहुंची थी। जब टीम होटल पहुंच गई और खिलाड़ियों के सामान उनको होटल पहुंचाए गए तो पता चला की एक दर्जन से ज्यादा बैट के अलावा क्रिकेट किट से दूसरे सामान चोरी हो गए हैं। जिसमें यह पता चला है कि काफी बैट ऐसे हैं, जिनकी कीमत 1-1 लाख से भी ज्यादा का है। हालांकि इस मामले को लेकर अभी तक एयरपोर्ट पुलिस के द्वारा कोई अधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है कि एफआईआर दर्ज हुई है या नहीं। सूत्रों के अनुसार दिल्ली कैपिटल टीम के कैप्टन डेविड वॉर्नर और टीम के खिलाड़ी यश ढुल सहित कई खिलाड़ियों के कई बैट और अन्य सामान चोरी हुए हैं। यह कैसे चोरी हुए इसको लेकर अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दिल्ली एयरपोर्ट पर जब सामान आया तब कार्गो से चोरी हुआ है या फिर बेंगलुरु में जब सामान रखा गया था, तब वहां से गायब हुआ है।

चिड़ियाघर में देखने को मिलेगी नन्हें शावकों की अठखेलियां, बाड़े में छोड़े गए 'अवनि' और 'व्योम'

नई दिल्ली। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान (चिड़ियाघर) में पहली बार सफेद बाघिन सीता के दो शावकों को उनके जन्म के बाद पिंजरे से बाड़े में लाया गया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बृहस्पतिवार को इन शावकों को बाड़े में छोड़ा और इनका नामकरण किया। उन्होंने मादा शावक का नाम अवनि और नर शावक का नाम व्योम रखा। वहीं, बाहर आते ही दोनों नन्हें शावक कुछ समय तक थोड़ा सुस्त लग रहे थे। लेकिन बाड़े के बाहर इन शावकों का दीदार कर रहे स्कूली छात्रों और अन्य पर्यटकों की तालियों की गड़गड़ाहट से इन शावकों ने कुछ देर बाद अठखेलियां शुरू कर दी।

कभी वे मां के पीछे-पीछे दौड़ते, तो कभी मां को छोड़ आपस में ही खेलने लगते। बाघिन सीता ने तो बाड़े में प्रवेश करते ही सीधा पानी में डुबकी लगा दी। नन्हें शावक भी अपनी मां के पीछे-पीछे पानी में डुबकी लगाने का प्रयास कर रहे थे। पानी में जाते ही वो तुरंत बाहर आ जाते। एक मौका तो ऐसा आया जब एक शावक पानी में बैठी बाघिन के ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहा था। लेकिन फिर असफल होने पर वो वहीं किनारे बैठ गया और उनकी मां फिर उन्हें वहीं से दुलार कर रही थी। उल्लेखनीय है कि आठ माह पहले ही दोनों शावकों का जन्म हुआ था। गर्मी को देखते हुए इनके बाड़े में वाटर स्प्रिंकलर, वाटर पूल की भी सुविधा है।

जानवरों के बाड़े में लगाए जा रहे कूलर और वाटर स्प्रिंकलर

राष्ट्रीय प्राणी उद्यान की निदेशक आकांक्षा महाजन ने बताया कि गर्मी बढ़ने के साथ जानवरों के बाड़े में कूलर और वाटर स्प्रिंकलर लगाए जा रहे हैं। वहीं, गर्मी में हाथी मिट्टी को खोदकर अपने ऊपर डालते हैं ऐसे में उनके बाड़े में मिट्टी को खुदवाया जा रहा है। साथ ही अन्य जानवरों के बाड़े में पानी के तालाब को रोजाना पानी से भरा जा रहा है। जानवरों को रसदार फल खिलाए जा रहे हैं। कुछ समय बाद तापमान बढ़ते ही भालू को आइसक्रीम भी खाने को दी जाएगी। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को चिड़ियाघर बंद रहता है। ऐसे में जिन दो शावकों को बृहस्पतिवार को छोड़ा गया है उन्हें शाम को वापस पिंजरे में ले जाया जाएगा और सोमवार को फिर से दोबारा बाड़े में छोड़ा जाएगा।

दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में बोरे में बंद मिला व्यक्ति का शव, मचा हड़कंप

नई दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में रात सड़क के पास बोरे में बंद 30 वर्षीय व्यक्ति का शव मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस

ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। मामले में आगे की जांच चल रही है।

चाकू से ताबड़तोड़ वार कर किशोर की हत्या

उधर, पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में चाकू से ताबड़तोड़ वार कर किशोर की हत्या कर दी। उसका शव उस्मानपुर दूसरा पुश्ता यमुना खादरमोहम्मद मुस्तफा, मां शबाना, एक छोटा भाई व बहन है। पुलिस को दिए बयान में शबाना ने बताया कि रात करीब 9.30 बजे आलम में खून से लथपथ हालत में मिला। मृतक की पहचान न्यू उस्मानपुर निवासी आलम के रूप में हुई है। किशोर के हाथ, गर्दन, कमर सहित शरीर पर कई जगह चाकू के निशान मिले हैं। शास्त्री पार्क थाना पुलिस हत्या की धारा में प्राथमिकी पंजीकृत कर मामले की जांच कर रही है।

अंतिम सफर को आसान बनाने का प्रयास, निशुल्क एंबुलेंस सेवा हुई शुरू

नई दिल्ली। बाहरी जिला पुलिस की ओर से जिले में निःशुल्क एंबुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है। शांति सेवा संगठन के सहयोग से 'अंतिम सफर' के नाम से शुरू की गई दो एंबुलेंस को उपायुक्त हरेंद्र सिंह ने कार्यालय परिसर में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन एंबुलेंस का इस्तेमाल शवों को उनके घरों तक पहुंचाने व लावारिस शवों को शवगृह तक पहुंचाने के लिए किया जाएगा। जरूरतमंदों को एंबुलेंस की निःशुल्क सुविधा प्रदान करवाकर पुलिस लोगों की मदद करने के लिए एक और कदम आगे बढ़ा रही है। पुलिस उपायुक्त हरेंद्र सिंह ने बताया कि कई बार सामने आया है कि मृतक के स्वजन के पास शव को घर तक ले जाने का भी किराया नहीं होता था। ऐसे जरूरतमंदों की मदद पुलिस कर्मी करते थे।पुलिस कर्मी मृतकों के अंतिम संस्कार में भी मदद करते थे। इसी के मद्देनजर अंतिम सफर को आसान बनाने का प्रयास किया गया है। इसके तहत एंबुलेंस से शवों को उनके मूल स्थानों तक पहुंचाया जाएगा।साथ ही पीसीआर कॉल के दौरान लावारिस मिले शवों को शवगृह तक भी पहुंचाया जाएगा।एंबुलेंस सेवा के नंबर जिले के प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित किए गए हैं। ताकि अधिक से अधिक लोग इस सेवा का लाभ उठा सकें। इस नेक काम के लिए उन्होंने संस्था को भी प्रोत्साहित किया।वहां अतिरिक्त उपायुक्त अमित वर्मा, एसीपी एसआर मीना भी मौजूद रहे।

अभिभावकों महंगी किताबें और स्कूल ड्रेस खरीदने को मजबूर करने वाले प्राइवेट स्कूलों पर एक्शन शुरू

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने अभिभावक को महंगी किताबें और स्कूल ड्रेस खरीदने को बाध्य करने वाले प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों को सरकार की ओर से कारण बताओ नोटिस भेजना शुरू कर दिया गया है और नोटिस का संतोषप्रद जवाब न मिलने पर शिक्षा निदेशालय संबंधित स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को तैयार है।

इस बाबत साझा करते हुए शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा कि अभिभावक से शिकायत आने पर संबंधित स्कूलों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। साथ ही डीडीई स्तर पर इसकी जाँच भी की जा रही है, यदि गाइडलाइन्स के उल्लंघन की स्थिति होती है तो इन स्कूलों पर दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट 1973 के संबंधित प्रावधानों की तहत कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि अभिभावक से आने वाली शिकायतों पर उन्होंने स्वयं नजर बना रखी है और शिक्षा निदेशालय को निर्देश दिए है कि अभिभावक की ओर से आने वाली हर शिकायत का तुरंत निवारण किया जाए ताकि उन्हें किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े।

उन्होंने बताया कि निदेशालय ने गाइडलाइन्स के उल्लंघन के मामले में सख्ती बरतते हुए अबतक 12

स्कूलों को कारण बताओं नोटिस भेजा है और साथ ही 6 अन्य स्कूलों के खिलाफ जांच भी की है।

शिक्षा निदेशालय के गाइडलाइन्स के तहत निजी स्कूलों को नए सत्र में प्रयोग में आने वाले किताबों व अन्य स्टडी मटेरियल की कक्षावार सूची नियमानुसार स्कूल की वेबसाइट और विशिष्ट स्थानों पर पहले से ही प्रदर्शित करनी होती है, ताकि अभिभावकों को इसके बारे में जागरूक किया जा सके। इसके अलावा स्कूल को अपनी वेबसाइट पर स्कूल के नजदीक के कम से कम पांच दुकानों का पता और टेलीफोन नंबर भी प्रदर्शित करना होता है जहां से अभिभावक किताबें और स्कूल ड्रेस खरीद सकें।

साथ ही स्कूल अभिभावक को किसी भी विशिष्ट विक्रेता से इन चीजों को खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। माता-पिता अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी दुकान से किताबें और यूनिफॉर्म खरीद सकते है। साथ ही शिक्षा निदेशालय की इस गाइडलाइन्स में ये भी स्पष्ट किया गया है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल कम से कम तीन साल तक स्कूल ड्रेस के रंग, डिज़ाइन व अन्य स्पेसिफिकेशन को नहीं बदल सकता है।

गुरुग्राम में 24 घंटे में मिले 517 नए मरीज, एक की मौत

गुरुग्राम। कोरोना संक्रमण से एक मरीज की मृत्यु हुई। यह इस महीने कोरोना से यह दूसरी मृत्यु है। इससे पहले छह अप्रैल को एक बुजुर्ग मरीज की मृत्यु हुई थी। 517 नए कोरोना मरीज मिले और 388 मरीज स्वस्थ हुए। संक्रमण दर 16.97 दर्ज की गई। गुरुग्राम में अप्रैल के 19 दिनों में 5359 कोरोना संक्रमित मरीज मिले चुके हैं। वहीं जिले में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 2660 हो गई है। 26 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं और अन्य सभी होम आइसोलेशन में इलाज करा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग मार्च 2020 से अबतक 38,74,780 लोगों की कोरोना जांच कर चुका है। जिसमें 3,07,239 मरीज मिले हैं और 3,03,546 मरीज स्वस्थ हुए हैं।

1033 मरीज की मृत्यु हुई है। गुरुग्राम में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी, मार्च समेत सात महीने में 3145 कोरोना संक्रमित मरीज मिले थे और सात मरीजों की मृत्यु हुई थी। इस वर्ष एक जनवरी से 31 मार्च तक 678 मरीज मिले है।

पांच दिन में मिले मरीज :

15 अप्रैल - 523 - 15.82
16 अप्रैल - 562 - 18 .43
17 अप्रैल - 461 - 16.38
18 अप्रैल - 461 - 16.36
19 अप्रैल - 517 - 16.97

था। उसकी मृत्यु हुई है। इस महीने अभी तक 5359 मरीज मिले हैं दो मरीजों की मृत्यु हुई है। कोरोना से

गुरुग्राम में अप्रैल के 19 दिनों में 5359 कोरोना संक्रमित मरीज मिले चुके हैं। वहीं जिले में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 2660 हो गई है। 26 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं और अन्य सभी होम आइसोलेशन में इलाज करा रहे हैं।

-- -- --

76 वर्षीय मरीज को दोनों कोरोनारोधी टीके लग चुके थे और एक निजी अस्पताल में इलाज ले रहा

घबराने की जरूरत नहीं है। बचाव पर ध्यान रखे।

- डा. विरेंद्र यादव, सिविल सर्जन

डीसीडब्ल्यू ने तेजाब मिलने के मामले में नगर निगम आयुक्त को नोटिस जारी किया

नई दिल्ली। दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) ने दिल्ली नगर निगम के सार्वजनिक शौचालयों में तेजाब के इस्तेमाल को लेकर नगर निगम आयुक्त को नोटिस जारी किया है। डीसीडब्ल्यू ने छह अप्रैल को दरियागंज में जीबी पंत अस्पताल के गेट नंबर आठ के सामने एक एमसीडी महिला शौचालय का निरीक्षण किया और शौचालय के अंदर खुले में एसिड से भरा 50 लीटर का डिब्बा मिला।

पूछताछ करने पर आयोग को सफाई कर्मचारी के साथ-साथ श्री राम ग्रामीण विकास संस्थान (जिसे एमसीडी द्वारा शौचालय परिसर के रखरखाव और संचालन के लिए अनुबंध दिया गया है) के एक कर्मचारी द्वारा सूचित किया गया था कि वे हर महीने शौचालयों को साफ करने के लिए एसिड खरीदते हैं।डीसीडब्ल्यू ने यह तुरंत तेजाब को दिल्ली पुलिस द्वारा जब्त करवाया और नगर निगम के अधिकारियों से शौचालयों में तेजाब की मौजूदगी के बारे में स्पष्टीकरण मांगते हुए समन जारी किया।

सिटी ज़ोन के वरिष्ठ अधिकारी डीसीडब्ल्यू के समक्ष उपस्थित हुए और एक लिखित उत्तर दिया जिसमें कहा गया है कि सार्वजनिक शौचालयों की सफाई के लिए तेजाब के उपयोग को रोकने के लिए नगर निगम द्वारा कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किए गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि शौचालयों की सफाई नगर निगम और एजेंसी के बीच अनुबंध के आधार पर लगाए गए नियमों और शर्तों के अनुसार एजेंसी द्वारा की जाती है। इसके अलावा, उन्होंने

शौचालय के रखरखाव और संचालन के लिए नगर निगम और एजेंसी (श्री राम ग्रामीण विकास संस्थान) के बीच अनुबंध समझौते की एक प्रति प्रदान की। अनुबंध समझौते के अवलोकन पर डीसीडब्ल्यू ने पाया कि उस पर 17.07.2017 को हस्ताक्षर किए गए थे, और 40 शौचालय परिसरों का रखरखाव एजेंसी को सौंपा गया था। नगर निगम द्वारा डीसीडब्ल्यू को दिए गए जवाब में अनुबंध समझौते (एमसीडी और एजेंसी के बीच) के नियम और शर्तों के नियम 36 की ओर इशारा किया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर एजेंसी द्वारा साप्ताहिक रूप से शौचालयों की सफाई के लिए एसिड का उपयोग नहीं किया जाता है, नगर निगम द्वारा एजेंसी पर प्रति दिन 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

दिल्ली डीसीडब्ल्यू की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा, यह बहुत चौंकाने वाला है। नगर निगम खुद अपने शौचालयों में तेजाब के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तेज़ाब के उपयोग, बिक्री और भंडारण के खिलाफ कड़े निर्देश जारी किए हैं। लेकिन एमसीडी तेजाब के इस्तेमाल को रोकने के बजाय जानबूझकर अपनी एजेंसियों को शौचालय की सफाई के लिए तेजाब का इस्तेमाल करने को कह रही है जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उक्त समझौते के नियमों और शर्तों में संशोधन किया जाना चाहिए और इस खंड को वापस लिया जाना चाहिए। नगर निगम को इस तरह के निर्देश जारी करने में शामिल अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए। इसके अलावा, नगर निगम को शौचालयों की सफाई के लिए तेज़ाब के उपयोग को रोकने के लिए शौचालय रखरखाव एजेंसियों को सख्त निर्देश जारी करना चाहिए।

प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए पर्यावरण मंत्री ने की समीक्षा बैठक

नई दिल्ली। दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए आज राज्य सचिवालय में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक में डीपीसीसी ,पर्यावरण विभाग और आईआईटी कानपुर के सम्बंधित प्रोफेसर और अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद राय ने बताया कि रीयल-टाइम सोर्स अपोरशमेंट स्टडी के डाटा पर विस्तृत चर्चा के लिए 15 मई को दिल्ली सचिवालय में 'सेव एनवायरनमेंट' राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी।

राय के अनुसार 'सेव एनवायरनमेंट' राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सीएक्यूएम, सीपीसीबी, सफर, यूएनईपी , आईएमडी, सीएसई, टेरी, वर्ल्ड बैंक आदि के साथ साथ उत्तरप्रदेश , पंजाब , राजस्थान , हरियाणा राज्यों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाएगा। साथ ही मोबाइल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग वैन को दिल्ली के 13 हॉट स्पॉट के प्रदूषण के वास्तविक स्रोतों का पता लगाने के लिए अलग अलग समय में लगाने का निर्देश दिया गया है।

समीक्षा बैठक के बारे में जानकारी देते हुए राय ने बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विंटर एक्शन प्लान के हिस्से के रूप में रियल टाइम सोर्स अपोर्शनमेंट स्टडी को शामिल किया था।

इसकी शुरुआत से दिल्ली में अब एक निश्चित समय पर प्रदूषण के वास्तविक कारणों का पता चल पा रहा है। ऐसा करने वाला दिल्ली देश का पहला राज्य बन गया है। रियल टाइम सोर्स अपोर्शनमेंट स्टडी से हर घंटे पता चल रहा है कि कहां, किस वजह से प्रदूषण है और अगले 3 दिन का घंटे के आधार पर फोरकास्ट का भी अनुमान लगाया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि रियल टाइम अपोरशमेंट स्टडी की सुपरसाइट से प्रदूषण के सही समय और कारकों की जानकारी मिलनी शुरू हुई है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए दिल्ली के हॉटस्पॉट्स में प्रदूषण बढ़ाने वाले मुख्य कारकों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए 5 मॉलिक्यूलर मार्कर भी लगाए गए है। फिलहाल यह नेटवर्क दिल्ली के द्वारका, जहांगीरपुरी, विवेक विहार , मुंडका और आनंद विहार में स्थापित किए गए है। साथ ही मोबाइल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग वैन को दिल्ली के 13 हॉट स्पॉट पर वास्तविक समय में प्रदूषण के स्रोतों का पता लगाने के लिए वहाँ अलग अलग समय पर स्थापित करने के निर्देश जारी किये गए है।

एलजी ने 1500 लोगों सौंपा नियुक्ति पत्र

नई दिल्ली। दिल्ली के नवनियुक्त सरकारी कर्मचारियों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी सरकार की कार्यप्रणाली पर प्रश्न खड़े किए। उन्होंने कहा कि पिछले 7-8 सालों में दिल्ली सरकार के अलग-अलग विभागों में महत्वपूर्ण पदों पर कोई नियुक्ति नहीं हुई, जो शर्मनाक है।

दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में एलजी ने कहा कि उन्हें दिल्ली का एलजी बने 10 महीने पूरे हो गए हैं। पदभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री से शिष्टाचार मुलाकात के समय उन्होंने सबसे पहले यही पूछा था कि दिल्ली में कितने पद खाली है? तब मैंने करीब 35 हजार पद खाली होने की बात कही थी। एलजी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने इन पदों पर जल्द से जल्द नियुक्ति करने की बात कही थी। आगे एलजी ने कहा कि इसको लेकर मुख्य सचिव के साथ मीटिंग की गई, जिसके बाद नियुक्तियों को लेकर शुरू हुई प्रक्रिया में तेजी आई थी। 10 महीने के अंदर 15 हजार लोगों को नौकरी दी गई। उन्होंने

नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए कहा कि यह नियुक्ति पत्र नहीं शपथ पत्र है। जिन्हें भी नियुक्ति पत्र मिला है, वह सरकार का हिस्सा बनने जा रहे हैं। कोई भी पद छोटा नहीं होता। उस पद पर बैठने वाला व्यक्ति उसे छोटा या बड़ा बनाता है। हमारी कोशिश थी कि परीक्षा बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हो।उन्होंने आगे कहा कि इससे पहले फरवरी में 1,200 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया था। यह संभव हो सका क्योंकि मुख्य सचिव और दिल्ली अधीनस्थ चयन सेवा समिति ने मेहनत से काम किया। सरकारी नौकरी सिर्फ आजीविका का साधन नहीं होना चाहिए। यह समाज की सेवा करने का एक मौका है। उन्होंने नियुक्त पत्र पाने वाले लोगों को बधाई देते हुए कहा कि हमें ईमानदारी से काम करने के लिए किसने रोका है। यह नियुक्ति पत्र साधारण नहीं है।

समारोह में उन्होंने बताया कि दिल्ली दमकल सर्विस में 2014 के बाद 500 कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है। इससे सेवा और सुदृढ़ होगी और फायर सर्विस के बल में वृद्धि होगी। इन सबकी नियुक्ति पहले ही होनी चाहिए थी। वहीं, दिल्ली के

दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में एलजी ने कहा कि उन्हें दिल्ली का एलजी बने 10 महीने पूरे हो गए हैं।

सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपल के पद 2010 से खाली थे, जिनके 324 पदों पर नियुक्ति हुई है। एलजी ने कहा कि सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपलों का नहीं होना चिंता का विषय है। दुख की बात है कि 2010 के बाद प्रिंसिपलों की बहाली नहीं हुई थी। आज उन्हें नियुक्ति पत्र देते हुए काफी प्रसन्नता हो रही है। वह जिम्मेदारी के साथ दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अपना योगदान देंगे।

एक मोबाइल से 300 सिम करते थे सक्रिय, गूगल एड के लिए हर महीने देते थे 10 लाख, ऐसे की करोड़ों की ठगी

नई दिल्ली। नई दिल्ली उत्तरी बाहरी जिला पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए साइबर ठगों का धंधा फर्जी सिम और गूगल एड (विज्ञापन) की मदद से चल रहा था। इसके जरिये आरोपितों ने देशभर में 2500 से अधिक लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी की।

पुलिस का यह भी कहना है कि गिरोह के शिकार लोगों की संख्या और अधिक हो सकती है। पूछताछ के आधार पर पुलिस को यह पता चला है कि लोगों से ठगी करने के लिए आरोपित गूगल एड देकर अपने नंबर को सबसे ऊपर रखते थे। इसके लिए हर महीने 10 लाख रुपये गूगल को देते थे।

गिरोह का सरगना निजामुद्दीन अंसारी बंगाल के नसीम से भारी मात्रा में फर्जी सिम खरीदता था। नसीम से पूछताछ में पता चला है कि वह यह सिम कार्ड बंगाल में अलग-अलग सिम कार्ड विक्रेताओं से खरीदता था। वह अलग-अलग साइबर ठगों को अब तक साढ़े बारह हजार फर्जी सिम कार्ड मुहैया करा चुका है। उसके घर से बरामद किए गए 21,761 सिम कार्ड में 16,000 सिम कार्ड हाल ही के दिनों में खरीदे गए हैं। ये सिम बिहार, ओडिशा, बंगाल और झारखंड के रहने वाले लोगों के नाम पर हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि कुछ सिम कार्ड विक्रेता और एक अन्य फर्जी सिम मुहैया कराने वाले की पहचान हुई है। पुलिस ने कुछ सिम कार्ड कंपनियों को पत्र लिख कर बरामद किए गए सिम कार्ड की जानकारी मांगी है।

सिम कार्ड विक्रेताओं की रहती है मिलीभगत

पुलिस अधिकारी ने बताया कि एक व्यक्ति अपने नाम पर नौ सिम खरीद सकता है। सिम कार्ड विक्रेता के यहां जब कोई सिम खरीदने जाता था तो उसके नाम पर दो से तीन सिम जारी करवा लेते थे।

इसकी जानकारी सिम खरीदने वाले को नहीं होती, चूंकि आधार कार्ड के जरिये केवाइसी की जाती थी। ऐसे में सत्यापन के नाम पर सिम खरीदने वाले को झांसा देकर अंगूठे को दो से तीन बार स्कैन करवाते थे। बाद में एक सिम दे देते थे बाकी दो सिम अपने पास रखते थे। इसके बाद इन सिमों को साइबर ठगों को पहुंचाया जाता था।

कई बैंक खातों और ई-वालेट का करते हैं इस्तेमाल

आरोपित ठगी की रकम को कई बैंकों और ई वालेट में डालते थे। यह सभी फर्जी पते पर होते हैं। एक बार ठगी की रकम बैंक खाते या ई-वालेट में आने के बाद रकम निकाल कर उसे उपयोग नहीं करते थे।

आईपीएल में आज घरेलू मैदान पर सनराइजर्स के खिलाफ जीत के लिए उतरेगी सीएसके

-स्टोक्स की होगी वापसी

नई दिल्ली (एजेंसी)। चेन्नई(ईएमएस)। आईपीएल में शुक्रवार को चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इस मैच में सीएसके अपने घरेलू मैदान पर जीत की प्रबल दावेदार मानी जा रही है। सीएसके ने पिछले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (आरसीबी) को हराया था। इससे भी उसका मनोबल बढ़ा हुआ है। इस मैच में ऑलराउंडर बेन स्टोक्स की वापसी से भी सीएसके की बल्लेबाजी और गेंदबाजी की धार बढ़ेगी। स्टोक्स चोटिल होने के कारण अब तक इस लीग से बाहर थे। स्टोक्स ने गत दिवस अभ्यास सत्र में भी भाग लिया था।

सीएसके के पास डेवोन कॉनवे और रुतुराज गायकवाड़ जैसी शानदार सलामी जोड़ी है। इसके अलावा उसके पास शिवम दुबे जैसा आक्रामक बल्लेबाज भी है। इन बल्लेबाजों के कारण ही उसके पिछले मैच में आरसीबी के खिलाफ जीत मिली थी। वहीं अनुभवी अजिंक्य रहाणे भी आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं, इससे भी चेन्नई को बल्लेबाजी बेहतर हुई है। चेन्नई की परेशानी गेंदबाजी को लेकर है। पिछले मैच में गेंदबाज प्रभावी नजर नहीं आये थे। इसके अलावा टीम का क्षेत्ररक्षण भी उम्मीद के अनुसार नहीं रहा है।

श्रीलंकाई तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना ने ही आरसीबी के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया था पर अन्य गेंदबाज विफल रहे। युवा तुषार देशपांडे के प्रदर्शन में सुधार आया है पर अगर टीम को सनराइजर्स के बल्लेबाजों पर अंकुश लगाना है तो उसके तीनों स्पिनरों महेश तीक्ष्णा, रविंद्र जडेजा और मोइन अली को और अच्छा प्रदर्शन करना होगा। आंकड़ों को देखें तो सीएसके ने सनराइजर्स के खिलाफ पिछले पांच में से चार मैचों में जीत हासिल की है और ऐसे में वह इस बार भी जीत चाहेगी। वहीं दूसरी ओर सनराइजर्स को पिछले मैच में मुंबई इंडियंस ने हराया था, ऐसे में उसका मनोबल गिरा हुआ है।

इसके बाद भी सनराइजर्स को अपने बल्लेबाजों से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। इसके लिए कप्तान एडेन मार्कराम को आगे

आकर जिम्मेदारी लेनी होगी। उसके सभी बल्लेबाजों को सीएसके के खिलाफ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा।

सनराइजर्स को पिछले मैच में पावर प्ले में विकेट गिरने से हार का सामना करना पड़ा था। तब टीम के मुख्य कोच ब्रायन लारा ने कहा था कि मध्यक्रम के किसी बल्लेबाज को अंत तक टिके रहना होगा। सनराइजर्स की बल्लेबाज मार्कराम के अलावा आक्रामक बल्लेबाज हैरी ब्रुक, वह वाशिंगटन सुंदर पर भी निर्भर रहेगी। अगर वह लय में खेलते है तो फिर सीएसके के गेंदबाजों को उन्हें रोकना कठिन होगा। इस लीग में अबतक सनराइजर्स के गेंदबाजों के प्रदर्शन में निरंतरता की कमी के कारण भी टीम को नुकसान हुआ है।

दोनो ही टीमें इस प्रकार हैं

चेन्नई सुपर किंग्स- महेंद्र सिंह धोनी (कप्तान और विकेटकीपर), डेवोन कॉनवे, रुतुराज गायकवाड़, अंबाती रायुडू, मोइन अली, बेन स्टोक्स, रवींद्र जडेजा, अजिंक्य रहाणे, सिसंडा मगाला, शिवम दुबे, ड्वेन प्रीटोरियस, अहय मंडल, निशांत सिंधु, राजवर्धन हैंगरगेकर, मिचेल सेंटनर, सुभांशु सेनापति, सिमरजीत सिंह, मथीसा पथिराना, महेश तीक्ष्णा, भगत वर्मा, प्रशांत सोलंकी, शेख रशीद, तुषार देशपांडे।

सनराइजर्स हैदराबाद- एडेन मार्कराम (कप्तान), अब्दुल समद, राहुल त्रिपाठी, ग्लेन फिलिप्स, अभिषेक शर्मा, मार्को यानसन, वाशिंगटन सुंदर, फजलहक फारूकी, कार्तिक त्यागी, भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन, उमरान मलिक, हैरी ब्रूक, मयंक अग्रवाल, हेनरिक क्लासेन , आदिल राशिद, मयंक मारकंडे, विवरांत शर्मा, समर्थ व्यास, संवीर सिंह, उपेंद्र यादव, मयंक डागर, नीतीश कुमार रेड्डी, अकील होसीन, अनमोलप्रीत सिंह।

विश्व मुक्केबाजी चैम्पियनशिप में भारत को शिव और दीपक से स्वर्ण की उम्मीदें

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय मुक्केबाज शिव थापा और दीपक भोरिया 30 अप्रैल से 14 मई तक उज्बेकिस्तान के ताशकंद में होने वाली पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैम्पियनशिप में भाग लेंगे। शिवा ने दोहा में 2015 में विश्व चैम्पियनशिप का कांस्य पदक जीता था। अब उनका लक्ष्य इस बार अपने पदक का रंग बदलना रहेगा। वह 63.5 किग्रा वजन वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। वहीं दीपक 51 किग्रा फ्लाईवेट वजन वर्ग में उतरेंगे। दीपक ने 2021 में स्ट्रेंड्जा मेमोरियल टूर्नामेंट में 2016 रियो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता और 2019 विश्व चैम्पियन उज्बेकिस्तान के शाखोबिदिन जोइरोव को हराकर सभी का ध्यान खींचा था। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ (बीएफआई) के अध्यक्ष अजय सिंह ने कहा, ''पुरुष टीम काफी कड़ी मेहनत कर रही है और मैं उन्हें बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनायें देता हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि हर मुक्केबाज बेहतर प्रदर्शन करेगा।''

भारतीय टीम 17 अप्रैल को ताशकंद के लिए रवाना हो गयी थी और विश्व चैम्पियनशिप से पहले कई देशों के अभ्यास शिविर में भी भाग लेगी। भारतीय टीम में अनुभवी एशियाई चैम्पियनशिप कांस्य पदक विजेता मोहम्मद हुसामुद्दीन भी शामिल हैं जो 57 किग्रा वजन वर्ग में हिस्सा लेंगे। तोक्यो ओलंपियन और 2019 एशियाई चैम्पियनशिप के रजत पदक विजेता आशीष चौधरी दूसरी बार इस प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे।

वहीं स्ट्रेंड्जा मेमोरियल मुक्केबाजी टूर्नामेंट में रजत विजेता गोविंद साहनी 48 किग्रा में उतरेंगे। इस टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक विजेता को दो लाख डॉलर, रजत पदक जीतने वाले को एक लाख डॉलर और दोनों कांस्य पदक विजेताओं को 50,000 डॉलर पुरस्कार राशि मिलेगी।

गावस्कर ने अर्जुन की प्रशंसा करते हुए कहा उसे विरासत में मिला है सचिन जैसा स्वभाव

मुम्बई (एजेंसी)। पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की प्रशंसा करते हुए कहा है कि उन्हें अपने पिता जैसा स्वभाव विरासत में ही मिला है। गावस्कर ने कहा, हर कोई उस शानदार प्रतिभा के बारे में बात करता है जो सचिन के करियर की शुरुआत में देखी गयी थी पर मुझे लगता है कि यह उनका स्वभाव था जो बिल्कुल ही अद्भुत था और यही स्वभाव अर्जुन को स्वभाव विरासत में मिला है।

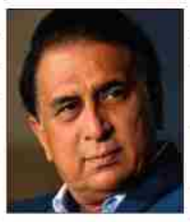

गावस्कर ने अर्जुन के एक अच्छे विचारक होने की भी सराहना की। उन्होंने कहा, यह हमेशा एक अच्छा संकेत होता है जब एक युवा खिलाड़ी टीम की ओर से अंतिम ओवर फेंकता है और डिलीवरी करता है। अर्जुन ने अंतिम ओवर फेंका और सनराइजर्स हैदराबाद को 20 रन बनाने नहीं दिए। इसके साथ ही उसने दूसरे ही मैच में भुवनेश्वर कुमार के रूप में अपना पहला आईपीएल विकेट भी लिया। अर्जुन एक होनहार युवा होने के साथ ही बाएं हाथ के तेज गेंदबाज भी हैं।

गावस्कर ने इसी के साथ ही अहमदाबाद में अपनी मैच विजेता पारी के लिए शिमरोन हेटमायर की सराहना करते हुए कहा कि वेस्टइंडीज के बल्लेबाज को बल्लेबाजी क्रम में ऊपर आना चाहिए। उन्होंने कहा, शिमरोन हेटमायर को राजस्थान रॉयल्स द्वारा एक फिनिशर के रूप में उपयोग किया गया है पर मेना मानना है कि उसे बल्लेबाजी क्रम में ऊपर भेजना चाहिए। इससे वह और अधिक स्कोर बना सकेंगे।

इंग्लैंड और जिम्बाब्वे के क्रिकेटर रहे बैलेंस ने खेल को अलविदा कहा

लंदन (एजेंसी)। इंग्लैंड और जिम्बाब्वे के पूर्व बल्लेबाज गैरी बैलेंस ने क्रिकेट के सभी रूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। बैलेंस ने इंग्लैंड और जिम्बाब्वे की ओर से शतक लगाकर रिकार्ड बनाया था। बैलेंस ने इंग्लैंड के लिए 16 एकदिवसीय और 23 टेस्ट मैच खेले। इसके बाद वह अपने जन्मभूमि जिम्बाब्वे लौट गये। जिम्बाब्वे की ओर से बैलेंस ने एक टेस्ट, एक टी20आई और पांच एकदिवसीय मैच खेले। करियर की बात करें तो उन्होंने दोनो देशों को मिलाकर कुल 5 टेस्ट शतक लगाए। उनका हाल में एक शतक अपने देश जिम्बाब्वे की ओर से लगाया था। यही उनका जिम्बाब्वे की ओर से एकमात्र टेस्ट था। उन्होंने अपनी पारी में नाबाद

137 रन बनाये थे।

बैलेंस ने कहा, काफी विचार के बाद मैंने तत्काल प्रभाव से पेशेवर क्रिकेट के सभी प्रारूपों को अलविदा कहने का फैसला किया है। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने जिम्बाब्वे की ओर से शीर्ष स्तर पर खेलना जारी रखने का अवसर देने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद थी कि जिम्बाब्वे जाने से मुझे खेल के लिए एक नई खुशी मिलेगी और मैं हमेशा जिम्बाब्वे क्रिकेट का आभारी रहूंगा कि उसने मुझे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी का मौका दिया और अपनी टीम में मेरा स्वागत किया।उन्होंने आगे कहा, हालांकि, मैं उस स्तर पर पहुंच गया हूं जहां मुझे अब पेशेवर खेल के लिए अपने को समर्पित करने की इच्छा नहीं है। इसलिए मुझे आगे बढ़ना चाहिए। मैं उन्हें आगे बढ़ने की हर सफलता की कामना करता हूं।

बैलेंस ने साल 2014 में अपनी शुरुआत करने के बाद इंग्लैंड के लिए 23 टेस्ट खेले और उनके लिए 1498 रन बनाए, जिसमें चार शतक और सात अर्धशतक शामिल थे। उन्होंने 2014 और 2015 सीज़न में यॉर्कशायर के साथ काउंटी चैंपियनशिप भी जीती थी। यॉर्कशायर में ही वह नस्लावाद के आरोपों को लेकर विवादों में भी रहे।

पहली बार भारत में खेला जाएगा अंतरराष्ट्रीय सर्फ ओपन

चेन्नई । भारत में पहली बार अंतरराष्ट्रीय सर्फ ओपन (डब्यूएसएल) का आयोजन इसी साल अगस्त में होगा। अंतरराष्ट्रीय सर्फ ओपन मामल्लापुरम में 14 से 20 अगस्त तक खेला जाएगा। इसमें एशिया और ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इस प्रतियोगिता के आयोजन की घोषणा करते हुए तमिलनाडु के खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि यह खेलों को बढ़ावा देने की दिशा में राज्य सरकार का एक और कदम है और इस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता से भारतीय खिलाड़ियों को अपनी क्षमता और प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर मिलेगा। उदयनिधि ने कहा, ''सर्फिंग ओलंपिक खेल है इसलिए यह प्राथमिकता बन गया है। यह अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता हमारे खिलाड़ियों को अपनी क्षमता दिखाने और हमारे देश को गौरवांवित करने का शानदार मंच देगा।''

कठिन हालातों में गेंदबाजी के लिए हमेशा तैयार हूं : आवेश

जयपुर । राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ आईपीएल मैच में अंतिम ओवर फेंकने वाले आवेश खान ने कहा कि मैं अपनी टीम के लिए मुश्किल हालातों में गेंदबाजी के लिए हमेशा ही उपलब्ध हूं। लखनऊ सुपर जायंट्स के आवेश ने इस मैच में अंतिम ओवर में राजस्थान के बल्लेबाजों पर अंकुश लगा लिया जिससे टीम 18 रनों का बचाव नहीं कर पायी। वहीं आवेश ने अंतिम ओवर में दो विकेट लिए। अवेश ने कहा, अगर हम पहले गेंदबाजी कर रहे हैं, तो मुझे पहला या दूसरा ओवर मिलता है और अगर हम बचाव कर रहे हैं तो मैं खेल की स्थिति के आधार पर चौथे या छठे ओवर जैसे अहम ओवर फेंकता हूं। मैंने अपने कप्तान और कोचों से भी कहा है कि आप मुझे कहीं भी गेंदबाजी करवा सकते हैं और मैं अपनी टीम के लिए कठिन ओवर फेंकने के लिए हमेशा से ही तैयार हूं। इसलिए मैं हमेशा यह सोचने की कोशिश नहीं करता कि मुझे कब गेंदबाजी करने का अवसर मिलेगा पर जब भी मुझे मौका मिलता है, मैं हमेशा टीम के लिए विकेट हासिल करने के लिए गेंदबाजी करता हूं। वहीं आईपीएल विशेषज्ञ आरपी सिंह का मानना है कि लखनऊ के कप्तान लोकेश राहुल पहले की तरह नहीं खेल रहे हैं। उन्होंने कहा, राहुल कभी भी इस तरह नहीं खेलते थे, उनका हमेशा एक अच्छा स्ट्राइक रेट होता था, वे विपक्षी टीम पर आक्रमण करते थे और अच्छे शॉट खेलते थे पर यहां उन्हें दबाव में खेलते हुए देखा गया। सिंह ने कहा, उन्होंने अपने कई शॉट मारना बंद कर दिया है। वह ज्यादा स्ट्राइक रोटेट करने की सोच रहा है, हो सकता है कि उसने अपनी भूमिका भी बदल ली हो, लेकिन वह उस तरह का खिलाड़ी नहीं है।

पाक के उभरते क्रिकेटर सईम माने जा रहे भविष्य के बाबर आजम

लाहौर(एजेंसी)। पाकिस्तान के उभरते हुए बल्लेबाज सईम अयूब को आने वाले समय का बाबर आजम माना जा रहा है। 20 साल के सईम ने हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज में अपना डेब्यू किया था। इस दौरे पर उनकी तरह कई युवाओं ने पाक की ओर से खिलाफ खेलना शुरु किया था। इस सीरीज में बाएं हाथ के बैटर सईम ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से सबका ध्यान खींचा है। सईम ने अफगानिस्तान के खिलाफ अंतिम टी20 में पारी की शुरुआत करते हुए 49 रन की पारी खेली थी। वहीं, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी पहले टी20 में सईम ने चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 28 गेंद में 47 रन बनाये थे। सईम मैदान के हर कोने में शॉट्स खेलते हुए शीर्ष क्रम में तेजी से रन बनाते हैं। सईम ने इसी साल पाकिस्तान सुपर लीग में डेब्यू करते हुए पेशावर जाल्मी की ओर से सत्र के 12 मैच में 165 की स्ट्राइक रेट से 341 रन बनाये। इसमें 36 चौके और 17 छक्के भी शामिल है।

सईम के लिए क्रिकेटर बनने का सफर आसान नहीं रहा। उनके पिता ने शौकिया तौर पर क्रिकेट एकेडमी में दाखिला कराया था पर धीरे-धीरे सईम अयूब का शौक बढ़ता गया। उन्होंने पहले क्लब स्तर और फिर ऐज ग्रुप क्रिकेट खेलना शुरू किया। हाल ही में सईम ने अपने इस सफर के बारे में बताया था। वहीं उनके पिता चाहते थे कि वह खेल छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान दें। सईम ने कहा था, पापा और बाकी घरवालों को ऐज ग्रुप क्रिकेट के बारे में बहुत पता नहीं था। उन्होंने मेरे शौक को देखते हुए एकेडमी में दाखिला करा दिया था। मैंने अंडर-16, अंडर-19 टूर्नामेंट खेले. आज से 4-5 साल पहले अंडर-16, अंडर-19 टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट में 50 हजार रुपये तक इनाम में मिलते थे।

इंग्लैंड में वार्नर का बल्ला रहा है खामोश, भारतीय टीम को मिलेगा लाभ

सिडनी (एजेंसी)। टेस्ट क्रिकेट में पिछले कुछ समय से खराब प्रदर्शन के बाद भी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डेविड वार्नर को भी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) फाइनल के लिए टीम में जगह मिली है। इसका लाभ भारतीय टीम को मिलेगा। इसका कारण ये है कि वार्नर आईपीएल से पहले भारतीय टीम के खिलाफ हुई टेस्ट सीरीज में नाकाम रहे थे। इसके अलावा यह भी देखा गया है कि इंग्लैंड में आमतौर पर वार्नर रन नहीं बना पाते हैं। इससे भारतीय टीम के गेंदबाजों के लिए उन्हें आउट करना आसान रहेगा। टेस्ट क्रिकेट में करियर औसत 45 का है लेकिन बात जब इंग्लैंड में खेलने की होती है तो यह गिरकर महज 26 का रह जाता है। इंग्लैंड में 13 मैचों की 25 पारियों में वार्नर 651 रन ही बना पाए हैं। उनके नाम इंग्लैंड में एक भी शतक नहीं है। खराब फार्म के कारण ही उन्हें एशेज सीरीज और इंग्लैंड में होने वाले आगामी डब्ल्यूटीसी फाइनल से पहले उन्हें रिटायरमेंट की सलाह दी जा रही थी पर इसके बाद भी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया सीए ने उन्हें अवसर दिया है।

विराट कोहली की कप्तानी वाली भारतीय टीम पिछली बार डब्ल्यूटीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में खिताब जीतने में असफल रही थी। अब उसका रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम का लक्ष्य कंगारुओं पर जीत हासिल कर खिताब अपने नाम करना रहेगा। बॉर्डर गावस?कर ट्रॉफी के दौरान भारतीय टीम इंडिया ने अपनी ही धरती पर ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराया था। इस दौरान भी वार्नर का बल्ला भी

खामोश ही रहा था। भारत को इसका सीधे तौर पर फायदा मिला था। ऐसे में वार्नर का ऑस्ट्रेलिया की टीम में होना भारत के लिए अच्छी खबर है।

कूल्हे की चोट के कारण मैड्रिड ओपन में नहीं खेलेंगे राफेल नडाल

मैड्रिड । दिग्गज टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल अभी कूल्हे की चोट से पूरी तरह नहीं उबर पाए हैं और इस कारण वह अगले सप्ताह मैड्रिड ओपन में भाग नहीं ले पाएंगे। बाईस बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन नडाल ऑस्ट्रेलियाई ओपन के दौरान चोटिल हो गए थे और उन्होंने जनवरी के बाद कोई टूर्नामेंट नहीं खेला है। चोट के कारण वह इंडियन वेल्स, मियामी, मोंटे कार्लो और बार्सिलोना टूर्नामेंट में नहीं खेल पाए थे। मैड्रिड ओपन सोमवार से शुरू होगा जिसमें नडाल पांच बार के चैंपियन हैं। नडाल ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर स्पेनिश में लिखा, 'इसके (चोट) कारण मुझे छह से आठ सप्ताह तक बाहर रहना था लेकिन मैं पिछले 14 हफ्ते से बाहर हूं।' उन्होंने कहा, 'हमने चिकित्सकों की राय पर अमल किया लेकिन उन्होंने जैसे कहा था उस तरह से मैं चोट से नहीं उबर पाया और अब हम स्वयं को मुश्किल परिस्थितियों में पा रहे हैं।' छत्तीस वर्षीय नडाल ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी कि वह 28 मई से होने वाले फ्रेंच ओपन में खेल पाएंगे या नहीं।

चैंपियंस लीग : मैनचेस्टर सिटी और रियाल मैड्रिड सेमीफाइनल में होंगे आमने-सामने

म्यूनिख। एर्लिंग हालैंड ने फिर से मैनचेस्टर सिटी की तरफ से गोल दागा जिससे उनकी टीम ने चैंपियंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में प्रवेश किया जहां उसका सामना रियाल मैड्रिड की मजबूत टीम से होगा। मैनचेस्टर सिटी ने बायर्न म्यूनिख के खिलाफ क्वार्टर फाइनल का दूसरा चरण 1-1 से ड्रा खेला लेकिन पहले चरण में 3-0 की दमदार जीत के कारण वह 4-1 के कुल योग से जीत दर्ज करके अंतिम चार में जगह बनाने में सफल रहा। पहला हाफ गोल रहित छूटने के बाद हालैंड ने 57वें मिनट में मैनचेस्टर सिटी को बढ़त दिलाई। यह इस सत्र में सिटी की तरफ से उनका 48वां गोल था। बायर्न की तरफ से जोशुआ किमिच ने 83वें मिनट में पेनल्टी को गोल में बदला लेकिन यह टीम को सेमीफाइनल में पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं था। मैनचेस्टर सिटी पहली बार चैंपियंस लीग जीतने की कोशिश करेगा लेकिन इसके लिए उसे मौजूदा चैंपियन रियाल मैड्रिड की कड़ी चुनौती से पार पाना होगा। रियाल मैड्रिड ने एक अन्य क्वार्टर फाइनल में चेल्सी को 4-0 के कुल योग से पराजित किया। सेमीफाइनल का पहला चरण मई में खेला जाएगा। पिछले साल रियाल मैड्रिड ने सेमीफाइनल में मैनचेस्टर सिटी को 6-5 से हराया था।

मैच से सबक लेकर आगे बढ़ना होगा: सैमसन

जयपुर(एजेंसी)। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ने आईपीएल में लखनऊ सुपरजाइंट्स के खिलाफ मिली 10 रनों की हार पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा है कि उनकी टीम को यह लक्ष्य हासिल कर लेना चाहिये था। सैमसन के अनुसार जिस प्रकार की उनकी टीम की बल्लेबाजी है उसको देखते हुए उसे यह लक्ष्य हासिल करना चाहिए था। इस मैच में 155 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए रॉयल्स की टीम सलामी बल्लेबाजों यशस्वी जायसवाल और जोस बटलर के बीच हुई 87 रन की साझेदारी के बाद भी मध्यक्रम के विफल होने के कारण लक्ष्य हासिल नहीं कर पायी।

सैमसन ने कहा, ''इस मैच के परिणाम से हमें निराश हो रही है पर इससे हमें सबक लेते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। हमारे पास जिस प्रकार का अच्छा बल्लेबाजी क्रम अभी है उसे देखते हुए यह लक्ष्य हासिल होना चाहिए था। विरोधी टीम ने हालांकि अच्छी गेंदबाजी करते हुए हालातों का अच्छा इस्तेमाल किया पर मेरा अब भी मानना है कि यह लक्ष्य हम हासिल कर सकते थे।'' पिच को लेकर सैमसन ने कहा, ''मैं इस तरह की कम उछाल वाली पिच की उम्मीद कर रहा था और मुझे लगता है कि हमें ऐसा ही कुछ मिला। अब आगे के मैचों में हमें समझदारी भरा क्रिकेट खेलने की जरूरत है और हम लगभग 9 से 10 ओवर तक काफी अच्छी स्थिति में थे पर इसके बाद बीच के ओवरों में टीम रन नहीं बना पायी और उसने विकेट खो दिये। जीत के लिए बीच के ओवरों में हमें एक अच्छे ओवर की जरुरत थी जो नहीं मिला। इसके अलावा विरोध टीम के गेंदबाजों को जीत का श्रेय दिया जाना चाहिये।

सुपरजाइंट्स की ओर से आवेश खान ने 25 रन पर तीन जबकि मार्कस स्टोइनिस ने 28 रन पर दो विकेट लिए। नवीन उल हक ने अच्छी गेंदबाजी करते हुए चार ओवर में केवल 19 रन दिए पर उन्हें कोई विकेट नहीं मिला।

असम-अरुणाचल के बीच सुलझा सीमा विवाद, अमित शाह की मौजूदगी में दोनों राज्यों के सीएम ने किए एमओयू पर हस्ताक्षर

नई दिल्ली, 20 अप्रैल (एजेन्सी)। असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच लंबे समय से चला आ रहा विवाद आखिरकार सुलझ गया। असम और अरुणाचल प्रदेश की सरकारों ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में दोनों राज्यों के बीच अंतरराज्यीय सीमा विवाद के निपटारे के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेमा खांडू ने गुरुवार को एमओयू पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लंबे ने समय से लंबित अंतरराज्यीय सीमा विवाद के निपटारे के लिए असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच समझौते पर हस्ताक्षर करने पर कहा कि दोनों राज्यों के बीच अंतरराज्यीय सीमा विवाद के समाधान के लिए समझौते पर हस्ताक्षर होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज हमने एक विकसित, शांतिपूर्ण और संघर्ष-मुक्त पूर्वोत्तर की स्थापना के लिए मील का पत्थर पार कर लिया है।

अमित शाह ने असम-अरुणाचल प्रदेश सीमा समझौते को 'ऐतिहासिक' घटना बताया। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही दशकों पुराने विवाद खत्म हो गए हैं। असम के सीएम हिमंत बिस्व सरमा ने कहा, सीमा समझौता 'बड़ा और सफल' क्षण। वहीं, अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू ने इसे 'ऐतिहासिक' बताया

हिमंत बिस्व सरमा ने कहा कि असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच 1972 से सीमा विवाद था। आज हमने सभी विवादों को बातचीत के जरिये सुलझा लिया है। गृह मंत्री शाह के मार्गदर्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से यह विवाद सुलझ गया है, यह एक मील का पत्थर साबित होगा।

असम कैबिनेट ने अरुणाचल प्रदेश के साथ दशकों से चल रहे सीमा विवाद के मुद्दे को हल करने के लिए राज्य सरकार की गठित 12 क्षेत्रीय समितियों द्वारा दी गई सिफारिशों को बुधवार (19 अप्रैल) को मंजूरी दी थी। कैबिनेट के फैसलों की घोषणा करते हुए असम के मंत्री अशोक सिंघल ने कहा था कि असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच लंबे समय से लंबित सीमा विवाद का मुद्दा सुलझने जा रहा है।

सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं लाभार्थी : मंत्री शर्मा

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 20 अप्रैल। सिक्किम के पशुपालन व पशु चिकित्सा सेवा विभाग द्वारा आज स्थानीय राज्य पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक में आधुनिक पशु चिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पशुपालन व पशु चिकित्सा मंत्री लोकनाथ शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे।

उनके साथ ही कार्यक्रम में गंगटोक नगर परिषद मेयर नेल बहादुर छेत्री, डिप्टी मेयर छिरिंग पाल्देन भूटिया, पानिहाउस पार्षद नोरबू तमांग, सिक्किम मिल्क यूनियन अध्यक्ष यम कुमार शर्मा, एएचवीएस विभागीय सचिव डॉ पी सेंथिल कुमार के अलावा अन्य पदाधिकारी एवं गणमान्य लोग भी मौजूद रहे।

इस अवसर पर अपने वक्तव्य में मंत्री शर्मा ने विभाग के प्रति सहयोग हेतु मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए राज्य सरकार एवं विभाग से पशुपालकों को मिल रहे लाभों एवं समर्थन का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न योजनाओं का भी उल्लेख करते हुए लाभार्थियों से उनका भरपूर उपयोग करने का आग्रह किया।

इसके अलावा, मंत्री ने निकट भविष्य में राज्य के सभी छह जिलों में पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक स्थापित करने और प्रत्येक जिले में छात्रों में पशुपालन के बारे में जागरुकता कार्यक्रम आयोजित करने की भी बात कही। इस दौरान उन्होंने सभी पशुपालकों को सेवाएं प्रदान करने हेतु दिन-रात काम करने वाले सभी फील्ड कर्मियों की सराहना की। वहीं उन्होंने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित पशुपालक तुलाराम उप्रेती का उदाहरण देते हुए अन्य सभी पशुपालकों को भी कड़ी मेहनत करने हेतु प्रोत्साहित किया।

वहीं इस दौरान एएचवीएस सचिव ने भी विभाग की विभिन्न उपलब्धियों पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट पेश की। इससे पहले, विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉ. देचेन ओंगमू कालेयोन ने मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामंग के संदेश को पढ़कर सुनाया। कार्यक्रम से पहले मंत्री शर्मा ने आधुनिक पशु चिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का शुभारंभ करने के लिए पट्टिका का अनावरण किया। इसके अलावा उन्होंने बीमारी जांच इकाई, आपातकालीन पशु चिकित्सा सेवाओं के लिए कॉल सेंटर का भी उद्घाटन किया। वहीं उन्होंने विभिन्न जिलों के सोलह हितग्राहियों को चेक एवं प्रोत्साहन राशि का वितरण भी किया।

सूरत कोर्ट के फैसले पर बीजेपी बोली- गांधी परिवार का टूटा अहंकार, पूरे देश में खुशी का महौल

नई दिल्ली, 20 अप्रैल (एजेन्सी)। 'मोदी सरनेम' मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से झटका लगा है। बीजेपी ने कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस को आड़े हाथ लेना शुरू कर दिया है।

मोदी सरनेम मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अपील को सूरत के सेशंस कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने को देश में संविधान के राज का प्रतीक बताते हुए भाजपा ने कहा है कि अदालत के इस फैसले से देश में खुशी का माहौल है।

भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने अदालत के फैसले पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए भाजपा मुख्यालय में मीडिया से बात करते हुए कहा कि सूरत की अपीलीय कोर्ट का जो फैसला आया है, उससे पूरे देश में खुशी का माहौल है। आज के इस फैसले से एक बात स्पष्ट होती है कि इस देश में संविधान का राज है, परिवार का राज नहीं है और किसी भी परिवार को विशेष दर्जा नहीं मिल सकता।

पात्रा ने कहा कि पिछड़े वर्ग के लिए राहुल गांधी ने आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था और ये सब करके गांधी परिवार को लगता था कि वो बचकर निकल जाएंगे, वह नहीं हो पाया। सूरत की अदालत के फैसले को गांधी परिवार के लिए बड़ा झटका और सबक बताते हुए उन्होंने आगे कहा कि इससे यह साबित होता है कि कानून सबके लिए बराबर है और कानून किसी के लिए भी अलग नहीं हो सकता।

भाजपा प्रवक्ता ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सूरत की अपीलीय कोर्ट के फैसले से यह बात साबित हो गई है कि ट्रायल कोर्ट का फैसला सही था और देश में लोकतंत्र नहीं बल्कि गांधी परिवार का घमंड समाप्त हो गया है।

उन्होंने कहा कि यह पिछड़े वर्ग और देश के लोगों के साथ-साथ न्यायपालिका के लिए भी उत्सव का समय है। न्यायपालिका ने इस फैसले से यह स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस और उसके समर्थक भले ही न्यायपालिका की कितनी भी आलोचना करें, सड़कों पर उतर कर अदालतों पर आरोप लगाएं, विरोध प्रदर्शन करें यहां तक कि विदेशों से भी बयान दिलवाएं लेकिन देश की न्यायपालिका इनके दबाव में आने वाली नहीं है।

'स्थिति बेहद तनावपूर्ण, हमारा ध्यान भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर', सूडान संकट पर विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, 20 अप्रैल (एजेन्सी)। सूडान में इस समय सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच खींचतान चल रही है। इस खींचतान के कारण वहां अबतक 270 लोगों की मौत हो चुकी है। दो हजार से अधिक लोग घायल है। तनावपूर्ण स्थिति में भारतीय भी फंसे हैं, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए विदेश मंत्रालय लगातार काम कर रहा है। गुरुवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि जमीन पर स्थिति बेहद तनावपूर्ण हैं। हमारा पूरा ध्यान लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर है। हम अलग-अलग माध्यमों से वहां के लोगों के संपर्क में हैं।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि खार्तूम में भारतीय दूतावास खुला हुआ है। लोगों की सुरक्षा के लिए अलग-अलग स्थानों से काम किए जा रहे हैं। दूतावास में अभी वहां कोई अधिकारी नहीं है। सभी अधिकारी सेवाएं सुनिश्चित कर रहे हैं।

मंत्रालय का कहना है कि सूडान की स्थिति के कारण विदेश मंत्री एस जयशंकर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव से मुलाकात कर सकते हैं। जमीन पर हम तैयार हैं। हमारी टीमें योजनाओं के साथ पास में ही तैनात हैं, लेकिन यह इसपर निर्भर करता है कि युद्ध विराम कब तक रहता है। निकासी के लिए सुरक्षित स्थान कब तक उपलब्ध हैं, लोगों की सुरक्षा के लिए यह भी काफी महत्वपूर्ण है।

सूडान में मिलिट्री और पैरामिलिट्री रेपिड सपोर्ट फोर्स (आरएसएफ) के बीच जारी लड़ाई में कम से कम 270 लोगों के मारने की खबर आ रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि वहां करीब 2600 से ज्यादा लोग घायल हैं। सूडान में सत्ता को लेकर संघर्ष की लड़ाई जारी है। रैपिड सपोर्ट फोर्सेज और नियमित सेना ने एक-दूसरे पर सीजफायर ब्रेक करने का आरोप लगाया है। सूडान में बढ़ती हिंसा के कारण अमेरिका, ब्रिटेन और ईयू ने लड़ाई खत्म करने की अपील की है। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने सूडानी सेना चीफ बुरहान और आरएफएफ चीफ डागालो को फोन करके सूडान में शांति स्थापित करने के लिए कहा है। रूसी एम्बेसी ने भी सीजफायर की अपील की है।

सूडान में जारी लड़ाई में एक भारतीय नागरिक अल्बर्ट ऑगस्टीन की भी मौत हो चुकी है। भारतीय मिशन ने ट्वीट कर बताया कि गोली लगने ने जान गंवाई है। अल्बर्ट सूडान में डल ग्रुप कंपनी के लिए काम करता था। शनिवार को हमले के दौरान सऊदी अरब की एक फ्लाइट में आग लग गई थी। जिसके बाद सऊदी और मिस्र ने सूडान जाने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है। चाड ने भी सूडान बॉर्डर बंद कर दिए हैं।

मई में भारत के गोवा में होने वाले एससीओ एफएम की बैठक में पाकिस्तान के शामिल होने पर विदेश मंत्रालय का कहना है कि किसी विशेष सदस्य पर ध्यान केंद्रित करना उचित नहीं होगा।

यूनीसेफ ने टीकाकरण के लिए की भारत की तारीफ, कहा- कोविड के बाद भी बना रहा टीकों का महत्व

नई दिल्ली, 20 अप्रैल (एजेन्सी)। यूनिसेफ ने कोरोना टीकाकरण को लेकर भारत की तारीफ की है। यूनिसेफ के अनुसार, भारत 55 में से उन तीन देशों में से एक है जहां कोविड-19 महामारी के बाद भी टीकों के महत्व की धारणा बनी रही या उनमें सुधार हुआ। हालांकि, भारत दुनिया के उन देशों में भी शामिल है जहां कई बच्चों को कोरोना वैक्सीन की एक भी खुराक (शून्य-खुराक) नहीं दी गई। भारत में ऐसे बच्चों की संख्या 27 लाख है, जिन्हें एक भी नियमित टीका नहीं दिया गया है।

यूनिसेफ के स्वास्थ्य विशेषज्ञ विवेक वीरेंद्र सिंह ने कहा, कोरोना महामारी के दौरान शून्य-खुराक वाले बच्चों की संख्या बढ़कर 30 लाख हो जाने के बावजूद, भारत 2020 और 2021 के बीच शून्य-खुराक वाले बच्चों की संख्या को कम करके 27 लाख तक लाने में सक्षम हुआ। इसके लिए चौथा गहन मिशन इन्द्रधनुष (आईएमआई) और व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के इसके निरंतर प्रावधान सहित सरकार द्वारा शुरू की गई अटूट राजनीतिक प्रतिबद्धता और निरंतर साक्ष्य-आधारित अभियानों को धन्यवाद देता हूं।

यूनिसेफ ने अपनी वार्षिक फ्लैगशिप रिपोर्ट 'द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन- 2023' में कहा है कि कोविड-19 महामारी के दौरान 55 देशों में से 52 देशों में बच्चों के लिए टीकों के महत्व की सार्वजनिक धारणा में गिरावट आई है। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक बच्चे के लिए टीकाकरण से पता चलता है कि महामारी की शुरुआत के बाद दक्षिण कोरिया, पापुआ न्यू गिनी, घाना, सेनेगल और जापान में बच्चों के लिए टीकों के महत्व की धारणा में एक तिहाई से अधिक की गिरावट आई है।

द वैक्सीन कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट द्वारा एकत्र और यूनिसेफ द्वारा प्रकाशित नए आंकड़ों में चीन, भारत और मैक्सिको ही ऐसे देश हैं जिनका अध्ययन किया गया है। अध्ययन के आंकड़ों ले संकेत मिला है कि इन देशों में टीकों के महत्व की धारणा बनी रही या इसमें सुधार हुआ।

रिपोर्ट में कहा गया है, अधिकांश देशों में 35 वर्ष से कम उम्र के लोगों और महिलाओं में महामारी की शुरुआत के बाद बच्चों के टीकों के बारे में कम विश्वास की रिपोर्ट दर्ज की गई है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि अध्ययन किए गए 55 देशों में से लगभग आधे देशों में 80 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाताओं ने टीकों को बच्चों के लिए महत्वपूर्ण माना, इसके बावजूद टीके को लेकर कम विश्वास देखा गया है। हालाकि, रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि कई कारकों के मिलने से पता चलता है कि वैक्सीन को लेकर हिचकिचाहट का खतरा बढ़ रहा है। इन कारकों में महामारी की प्रतिक्रिया के बारे में अनिश्चितता, भ्रामक जानकारी तक बढ़ती पहुंच, विशेषज्ञता के विश्वास में कमी और राजनीतिक ध्रुवीकरण शामिल हैं।

यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक कैथरीन रसेल ने कहा, महामारी के चरम पर वैज्ञानिकों ने तेजी से ऐसे टीके विकसित किए जिन्होंने अनगिनत लोगों की जान बचाई। लेकिन इस ऐतिहासिक उपलब्धि के बावजूद सभी प्रकार के टीकों को लेकर भय और गलत सूचना वायरस की तरह व्यापक रूप से प्रसारित हुई।

अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस को लेकर मंत्री लोकनाथ शर्मा ने की तैयारी बैठक

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 20 अप्रैल। सिक्किम के श्रम मंत्री लोकनाथ शर्मा ने आगामी आज स्थानीय श्रम भवन के सभागार में आगामी अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस की तैयारी को लेकर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इसमें राज्य के ऊर्जा व परिवहन मंत्री एमएन शेर्पा विशेष रूप से उपस्थित रहे। गौरतलब है कि श्रम दिवस समारोह पाकिम जिलान्तर्गत कुमरेक के गुलमोहर पार्क में मनाया जाएगा।

बैठक में निर्धारित कार्यक्रम के लिए चल रही तैयारियों एवं विभिन्न घटकों पर गहन चर्चा हुई। इस दौरान मंत्री शर्मा ने सभी को अपनी जिम्मेदारियों का पूरी प्रतिबद्धता से निर्वहन करने की सलाह देते हुए सभी स्तरों पर आवश्यक अभ्यासों को क्रियान्वित करने में कोई कसर नहीं छोड़ने पर जोर दिया। वहीं मंत्री शेरपा, जो श्रमिक मोर्चे के प्रभारी भी हैं, ने अपने अनुभव और सलाह साझा किये।

आज की उक्त बैठक में विभागीय सलाहकार मनोज प्रधान, अध्यक्ष श्रीमती गंगा परसैन, श्रम विभाग के पीआर सचिव सीएस राव, सचिव कर्मा नामग्याल भूटिया, विशेष श्रम आयुक्त डीएस कुंवर और अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। इससे पहले पीआर सचिव राव ने पिछली बैठकों के अंशों और सौंपी गई उपसमितियों द्वारा अब तक की गई प्रगति की जानकारी दी। वहीं सचिव कर्मा नामग्याल ने कार्यक्रम की उल्लेखनीय बारीकियों से अवगत कराया।

मानहानि केस में राहुल गांधी की सूरत कोर्ट से याचिका खारिज

सूरत, 20 अप्रैल (एजेन्सी)। गुजरात के सूरत की एक अदालत ने गुरूवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आपराधिक मानहानि के एक मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने के अनुरोध वाली याचिका खारिज कर दी।

आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी ठहराये जाने, और दो साल कैद की सजा सुनाए जाने के कारण राहुल गांधी को लोकसभा सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

अदालत ने कहा कि उन्हें (राहुल को) अपने शब्दों को लेकर अधिक सावधान रहना चाहिए था क्योंकि वह संसद के सदस्य और देश की दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष थे।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर.पी. मोगेरा की अदालत ने उनकी मोदी उपनाम संबंधी टिप्पणी पर 2019 के मानहानि मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने के अनुरोध वाली याचिका खारिज कर दी।

न्यायाधीश ने कहा कि अपीलकर्ता जैसे व्यक्ति से नैतिकता के उच्च स्तर की अपेक्षा की जाती है। उन्होंने कहा कि निचली अदालत ने एक सजा दी थी जो कानून में अनुमेय थी।

गत 23 मार्च को सूरत की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिया था और दो साल के कारावास की सजा सुनाई थी जिसके एक दिन बाद जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत उन्हें लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दे दिया गया।

बृहस्पतिवार को अपने आदेश में अतिरिक्त सत्र अदालत ने यह भी कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 (3) के तहत सांसद के रूप में गांधी को हटाने या अयोग्य घोषित किए जाने को अपरिवर्तनीय या अपूरणीय क्षति या नुकसान नहीं कहा जा सकता है।

न्यायाधीश मोगेरा ने अपने आदेश में कहा, अपीलकर्ता के मुख से निकले कोई भी अपमानजनक शब्द व्यथित व्यक्ति को मानसिक पीड़ा पहुंचाने के लिए पर्याप्त हैं।

अदालत ने कहा कि अपमानजनक शब्दों का उच्चारण करने और चोरों के साथ मोदी उपनाम वाले व्यक्तियों की तुलना करने से निश्चित रूप से मानसिक पीड़ा हुई होगी और शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी की प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ होगा, जो सामाजिक रूप से सक्रिय हैं और सार्वजनिक रूप से लोगों से मिलते-जुलते हैं।

सूरत पश्चिम से सत्ताधारी भाजपा के विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत आपराधिक मानहानि के लिए शिकायत दर्ज की थी। यह शिकायत राहुल द्वारा 13 अप्रैल, 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान की गई एक टिप्पणी के लिये की गई थी। राहुल ने कोलार में चुनावी रैली के दौरान कहा था कि सभी चोरों का उपनाम मोदी कैसे होता है?

अदालत ने कहा, यह कोई विवादित तथ्य नहीं है कि अपीलकर्ता संसद सदस्य और दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का अध्यक्ष था, और अपीलकर्ता के ऐसे कद को देखते हुए, उसे अपने शब्दों को लेकर अधिक सावधान रहना चाहिए था, जिसका लोगों के मन पर व्यापक प्रभाव होगा।

अदालत ने कहा कि अपीलकर्ता के वकील यह साबित करने में विफल रहे कि उनकी (राहुल की) दोषसिद्धि पर रोक न लगाकर उन्हें चुनाव लड़ने के अवसर से वंचित करने से उन्हें अपरिवर्तनीय और अपूर्णीय क्षति होगी।

न्यायाधीश ने गांधी के वकील के इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि इस तरह एक समुदाय के खिलाफ मानहानि नहीं हो सकती।

अदालत ने कहा, हो सकता है कि समुदाय की प्रतिष्ठा न हो, लेकिन प्रतिष्ठा केवल व्यक्तिगत सदस्यों की होगी। जब मानहानिकारक मामला एक निश्चित वर्ग या समूह के प्रत्येक सदस्य को प्रभावित करता है, तो उनमें से प्रत्येक या सभी कानून का सहारा ले सकते हैं।

अदालत ने कहा, निचली अदालत द्वारा दर्शाए गए प्रथम दृष्टया साक्ष्य और टिप्पणियों को देखते हुए, यह पता चलता है कि गांधी ने आम जनता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ अपमानजनक टिप्पणी की थी और मोदी उपनाम वाले व्यक्तियों की तुलना चोरों से की थी।

डियर साप्ताहिक लॉटरी
नदिया निवासी ने
₹1 करोड़ जीते

नदिया, पश्चिम बंगाल के श्री स्वपन घोष ने **11.03.2023** को सम्पन्न हुए डियर साप्ताहिक लॉटरी के ड्रॉ में प्रथम पुरस्कार के तौर पर रु. 1 करोड़ जीते हैं। उनकी विजेता टिकट का नंबर **83C 22062** है। उन्होंने कोलकाता स्थित नागालैंड स्टेट लॉटरीज के नोडल अधिकारी के पास प्राइज क्लेम फॉर्म के साथ अपनी पुरस्कार-विजेता टिकट जमा कर दी है। ''एक करोड़पति बनने का मेरा सपना केवल कुछ रुपए खर्च करने के द्वारा सच हो गया है। मेरे द्वारा खरीदी गई डियर लॉटरी ने मुझे एक करोड़पति बना दिया है। मेरे जैसे व्यक्ति के लिए एक करोड़पति बनने का डियर लॉटरी ही एकमात्र उपलब्ध रास्ता है। डियर लॉटरी सभी क्षेत्रों में करोड़पति बनाकर आश्चर्यचकित कर रही है।'' विजेता ने कहा।

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक : सत्येन्द्र नाथ सिंह एवं मुद्रकः नूतन वर्मा द्वारा प्राइम प्रिंटर्स, प्रिमुला कॉटेज, चर्च रोड, गंगटोक से मुद्रित एवं रतना निवास, मेट्रो प्वाइंट, नेशनल हाईवे 10, गंगटोक (पूर्व सिक्किम) से प्रकाशित।
सम्पादक - सत्येन्द्र नाथ सिंह, कार्यकारी सम्पादक - अश्विनी आनंद, मोबाइल नं. : 9474355832, 9609024017, फोन नं. : 03592-204174, पोस्टल रजि. सं. : WB/SKM/110/07-09, e-mail ID : anugamini@gmail.com